



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092020-222089
CG-DL-E-29092020-222089

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राप्तिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268]
No. 268]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2020/आश्विन 6, 1942
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2020/ASVINA 6, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2020

मामला सं. एसजी-08/2019

विषय: भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय) नियमावली, 2017 के तहत कोरिया से भारत में "फ्यौलिक एनहाइड्राइड" के आयातों के संबंध में द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच की अंतिम जांच परिणाम।

फा. सं. 22/8/2019-डीजीटीआर.—क.

मामले की पुष्टिग्रन्थि

1. भारत गणराज्य और कोरिया सरकार के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईपीए) के अनुच्छेद 2.22 और भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार (द्विपक्षीय सुरक्षा उपाय) नियमावली, 2017 (जिसे यहां आगे "नियमावली" अथवा "द्विपक्षीय सुरक्षा नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स आई जी पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और मैसर्स थिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" कहा गया है) ने कोरिया गणराज्य (जिसे यहां आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) से फ्यौलिक एनहाइड्राइड (पीएन) (जिसे यहां आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के बढ़े हुए आयातों के संबंध में द्विपक्षीय सुरक्षा

जांच की शुरूआत के लिए सीईपीए और द्विपक्षीय सुरक्षा नियमावली के अनुसार व्यापार सुधार महानिदेशक (जिसे यहां आगे "प्राधिकारी" अथवा "महानिदेशक" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर नियमावली के अनुसार जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 1 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना संख्या एसजी-08/2019 जारी की।
3. घरेलू उद्योग द्वारा अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के लिए किए गए अनुरोध की जांच की गई थी और अनंतिम रूप से यह निर्धारित किया गया था कि नाजुक परिस्थितियां मौजूद थीं जिसमें अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना आवश्यक कर दिया। प्रारंभिक जांच-परिणाम दिनांक 11 मई, 2020 की अधिसूचना सं. 22/8/2019-डीजीटीआर के माध्यम से जारी किया गया था जिसमें कोरिया के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई थी। केन्द्र सरकार ने दिनांक 6 जुलाई, 2020 की अधिसूचना सं. 29/2020-सीमा शुल्क के माध्यम से सीईपीए के अंतर्गत दी गई रियायतों को समाप्त कर अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाया और 200 दिनों की अवधि के लिए कोरिया के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर सीमा शुल्क की दर को बढ़ाकर 7.5% कर दिया।

ख. प्रक्रिया

4. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:
 - क. प्राधिकारी ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2019 की जांच की शुरूआत संबंधी अधिसूचना की प्रति वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों में केंद्र सरकार, भारत में कोरिया गणराज्य के दूतावास के माध्यम से कोरिया सरकार, संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों तथा निर्यातकों और आवेदन पत्र में उल्लिखित ज्ञात आयातकों तथा अन्य पक्षकारों को उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(2) के अनुसार भेजी।
 - ख. आवेदकों द्वारा दायर आवेदन पत्र के अगोपनीय पाठ की प्रति वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों में केंद्र सरकार, भारत में कोरिया गणराज्य के दूतावास के माध्यम से कोरिया सरकार और संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों तथा निर्यातकों को नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार उपलब्ध कराई गई थी।
 - ग. प्राधिकारी ने संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच शुरू किए जाने की सार्वजनिक सूचना की प्रति अग्रेषित की और नियमावली के नियम 5(4) के अनुसार निर्धारित स्वरूप एवं तरीके से प्रश्नावली का उत्तर दायर करने तथा तीस दिन के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार देने का अवसर प्रदान किया:
 - i. एक्युंग पैट्रोकेमिकल कं. लि.
 - ii. एलजी पैट्रोकेमिकल, यियोचोन
 - iii. हनवा केमिकल कारपोरेशन
 - iv. ओसीआई कंपनी लिमिटेड
 - घ. जारी प्रश्नावली के उत्तर में सभी चार उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए।
 - ड. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार, आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक की प्रश्नावलियां भेजी:
 - i. क्रै वैली रेसिन्स इंडिया लि.
 - ii. गुडलेस नेरोलेस पेंट्स लि.
 - iii. गार्गी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - iv. हिंदुस्तान इंसेकटीसाइड्स लिमिटेड
 - v. केमरॉक इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स लि.
 - vi. शालीमार पेंट्स लिमिटेड
 - vii. यू. के. पेंट्स इंडिया प्रा. लि.

च. उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं:

- i. संदीप ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लि.
- ii. यूनिटी ऑर्गेनिक्स प्रा. लि.
- iii. निशांत ऑर्गेनिक्स प्रा. लि.
- iv. धनलक्ष्मी पिंगमेंट्स प्रा. लि.
- v. केसर पैट्रोप्रोडक्ट्स लि.
- vi. मजदा कलर्स लि.
- vii. शिव डाइस्टफ इंटरमीडिएट इंडस्ट्रीज
- viii. ए-वन फ्लैलो कलर्स प्रा. लि.
- ix. ए-वन केमिकल्स लिमिटेड
- x. नारायण ऑर्गेनिक्स प्रा. लि.
- xi. नारायण इंडस्ट्रीज
- xii. पीसीएल ऑयल एंड सॉल्वेंट्स लि.
- xiii. केएलजे प्लास्टिसाइजर्स लि.
- xiv. रचना प्लास्टिसाइजर्स
- xv. पायल पॉलीप्लास्ट प्रा. लि.
- xvi. एशियन पेंट्स लिमिटेड
- xvii. कनसाई नेरोलेक पेंट्स लिमिटेड
- xviii. शालीमार पेंट्स लि.
- xix. बर्जन पेंट्स इंडिया लि.

छ. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को भी प्रश्नावली भेजी। घरेलू उद्योग ने अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए।

ज. निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने जांच की शुरूआत की अधिसूचना का उत्तर देते हुए अनुरोध दायर किए:

- i. केमेक्सिल (बेसिक केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड डाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल)
- ii. द गुजरात डाइस्टफ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
- iii. एकुंग पैट्रोकेमिकल कं. लि., हनवा केमिकल कारपोरेशन, ओसीआई कंपनी लि., एलजी केम. लि. की ओर से कोरिया पैट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एसोसिएशन।
- iv. कोरिया सरकार
- v. इंडियन पेट एसोसिएशन
- vi. केएलजे प्लास्टिसाइजर्स लि.,
- vii. पायल पॉलीप्लास्ट प्रा. लि.,
- viii. रचना प्लास्टिक्स
- ix. पीसीएल ऑयल और सॉल्वेंट्स लि. की ओर से सामूहिक अनुरोध।

- ज. प्रारंभिक जांच परिणाम को प्रकाशित किए जाने के बाद, महानिदेशक ने इस नियमावली के नियम 5(6) के संदर्भ में 11 अगस्त, 2020 को एक मौखिक सुनवाई आयोजित की जहां सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर उपलब्ध कराया गया था। उसके बाद, हितबद्ध पक्षकारों को लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर टिप्पणियां देने के लिए अवसर उपलब्ध कराया गया था। मौखिक सुनवाई के पश्चात हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर किए गए लिखित अनुरोधों की प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी। हितबद्ध पक्षकारों को अन्यक हितबद्ध पक्षकारों के लिखित अनुरोधों के संबंध में प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, को प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी उपलब्ध कराया गया था।
- ज. प्रारंभिक जांच परिणाम को प्रकाशित किए जाने के बाद, निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा टिप्पणियां प्रस्तुत की गई थीं:
- i. कोरिया सरकार (जीओके)
 - ii. इंडियन पेंट एसोसिशन
 - iii. कोरिया पैट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एसोसिएशन
 - iv. केएलजे प्लास्टिसाइजर्स लि.,
 - v. पायल पॉलीप्लास्ट प्रा. लि.,
 - vi. रचना प्लास्टिक्स
 - vii. पीसीएल ऑयल और सॉल्वेंट्स लि.
- ट. मौखिक सुनवाई के बाद लिखित अनुरोध और प्रत्युत्तर निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे:
- i. घरेलू उद्योग
 - ii. कोरिया सरकार
 - III. इंडियन पेंट एसोसिशन
 - IV. कोरिया पैट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एसोसिएशन
 - V. दि गुजरात डाइस्टफ मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन
 - VI. इंडियन प्लास्टिसाइजर्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईपीएमए)
- ठ. प्राधिकारी ने इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।
- ड. कोरिया की सरकार (जीओके) ने परामर्श के अवसर का लाभ उठाया जो 15 सितंबर, 2020 को आयोजित की गई थी। जीओके द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं की जांच और उनका समाधान किया गया है। इसके अलावा, कोरिया की सरकार द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को पहले भी लिखित अनुरोधों के द्वारा उठाया गया है और उन पर वर्तमान जांच परिणामों में विधिवत् विचार और उनका उपयुक्त रूप से समाधान भी किया गया है।
- ढ. इस जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का समाधान प्राधिकारी द्वारा जहां भी संगत पाया गया, इस अंतिम जांच परिणाम में किया गया है।
- ग. आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध
- ग.1 विचाराधीन उत्पाद
5. आवेदकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. जांचार्धीन उत्पाद एचएस कोड 29173500 के तहत आने वाला "फैलिक एनहाइड्राइड" है। विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग सामान्यतः फैलिक इंस्टर का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जो प्लास्टिसाइजर के रूप में काम करता है।
- ख. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किया जा रहा उत्पाद आयातित उत्पाद की समान वस्तु है। घरेलू उत्पाद आयातित उत्पाद से तुलनीय है।
6. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अन्य हितबद्धपक्षकारों द्वारा कोई भी अनुरोध नहीं किया गया।
- ग.2 घरेलू उद्योग**
7. आवेदक ने यह तर्क दिया है कि उनके अलावा भारत में दो मौजूदा उत्पादक नामतः एसआई ग्रुप लिमिटेड और एशियन पेंट हैं। एशियन पेंट्स ने जुलाई, 2017 को अपने संयंत्र को अस्थाई रूप से बंद कर दिया है।
8. घरेलू उद्योग के क्षेत्र के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।
- ग.3. गोपनीयता**
9. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए हैं:
- क. आवेदकों ने अपने आवेदन में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि वे ऑकड़े जो पाटनरोथी जांच के अंतिम जांच परिणाम में उपलब्ध थे, को प्रकट नहीं किया गया है। इसके अलावा, व्यापार नोटिस 10/2018 की अपेक्षाओं का भी अनुपालन नहीं किया गया है।
- ख. समायोजन योजना अस्पष्ट, अत्यधिक रूप से गोपनीय है। आवेदक समायोजन योजना का संक्षिप्त किया हुआ/अगोपनीय पाठ उपलब्ध नहीं करा पाए जिसने हितबद्ध पक्षकारों को समायोजन योजना की व्यवहार्यता पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर से वंचित कर दिया है।
- ग. घरेलू उद्योग ने क्षमता के विस्तार के बारे में गोपनीयता का दावा किया है। हालांकि इसे मौखिक सुनवाई में प्रकट नहीं किया गया था। इस कारण से, इस सूचना को गोपनीय के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।
- ग.4. विविध अनुरोध**
10. आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार हैं:
- क. समायोजन योजनाओं के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वे कीमतें कम करने के लिए उपाय कर रहे हैं। आईजी पैट्रोकेमिकल्स ने समायोजन योजना दी है जिसमें मौजूदा उत्प्रेरक को बदलकर कझी सामग्री लागत में कमी करने संबंधी कार्रवाई योजना, विद्युत एवं ईंधन लागत में वसूलियों की कमी में सुधार, क्षमता अभिवृद्धि तथा मौजूदा संयंत्रों की यूटिलिटियों को एकीकृत करने, प्रशासनिक खर्चों, कार्मिक लागत और वित्तीय लागत के निमित्त लागतों को कम करने के प्रयास शामिल हैं। थिरुमलाई केमिकल्स ने एक समायोजन योजना दी है जिसमें उच्चतम क्षमता तथा दक्षता के लिए उपस्करों का उन्नयन कर लागत में कमी, उत्पादन में सुधार, ऊर्जा लागतों में कमी, तेल खपत में कमी, वेतन एवं मजदूरियों, भंडार तथा अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों, मरम्मत एवं रख-रखाव तथा प्रशासनिक ऊपरी खर्चों में कमी शामिल है।
- ख. ये उपाय घरेलू उद्योग को अपनी समायोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से 4 वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए आवश्यक है।
- ग. आवेदक विचाराधीन उत्पाद के लिए अपनी क्षमताओं का विस्तार करने की प्रक्रियाओं में है जो 4,84000 मी.टन पहुंचने की आशा है जिसके लिए उन्होंने बहुत अधिक राशि खर्च की है। उसके बाद क्षमता भारत में मांग की तुलना में अधिक हो गई।
- घ. विगत में जब अनुरोध की गई अवधि के लिए संरक्षण नहीं दिया गया था, घरेलू उद्योग अपने आप को समायोजित करने में सक्षम नहीं थे।

- ड. क्षमता के विस्तार का निर्णय रातों रात नहीं लिया जाता है बल्कि यह एक अवधि में होता है। क्षमता का विस्तार करने का निर्णय तब लिया गया था जब घरेलू उद्योग को लाभ हो रहा था।
- च. क्षमता का विचार यह सुनिश्चित करेगा कि भारत में क्षमता देश में मांग की तुलना में अधिक होगी।
- छ. पिछला पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को संरक्षण नहीं दे रहा था बल्कि विदेशी उत्पादकों द्वारा पाटन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ही था।
- ज. आवेदकों ने उचित प्रतिस्पर्धा को पूर्व स्थिति में लाने के लिए कोरिया से आयातों पर रियायतों को स्थगित करने के लिए ही अनुरोध किया है।
- झ. बीआईएस मानक ग्राहकों को केवल बेहतर गुणवत्ता उपलब्ध कराएगा।
- ञ. उपभोक्ताओं ने ग्राहक की पूछताछ का उत्तर नहीं देते हुए उत्पादकों के बारे में निराधार आरोप लगाए हैं।
11. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार हैं:
- क. आवेदक ने इस नियमावली की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है।
- ख. वर्तमान जांच समाप्त कर दी जानी चाहिए क्योंकि वैध द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया है क्योंकि रक्षोपाय जांच के लिए अपेक्षित मानदंड बहुत ऊँचे हैं।
- ग. इस आवेदन में खामियां हैं क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराया गया आंकड़ा जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में पहचान की गई अवधि के अनुरूप नहीं है।
- घ. आवेदकों ने द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच की शुरुआत करने के लिए शर्तों को सिद्ध करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिए हैं। अनुच्छेद 2.22 में निर्धारित चार शर्तों को पूरा नहीं किया गया है।
- ड. जांच की शुरुआत द्विपक्षीय रक्षोपाय नियमावली के नियम 4(2)ख) जो जांच की शुरुआत के पहले के चरण में दायित्वों से संबंधित है, के अंतर्गत वैध और अनुरूप नहीं हैं। इस जांच की शुरुआत के समय समायोजन योजना उपलब्ध नहीं कराने की खामियों को बाद में समायोजना उपलब्ध कराकर दूर नहीं किया जा सकता है।
- च. पूर्व के वैधिक रक्षोपाय जांच में घरेलू उद्योग ने एक समान समायोजन योजना प्रस्तुत की थी जिसे इसने लागू नहीं किया। इसे महानिदेशालय रक्षोपाय द्वारा रक्षोपाय संरक्षण नहीं देने के लिए एक मुख्य कारण के रूप में माना गया था।
- छ. समायोजन योजना पर महानिदेशालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण द्विपक्षीय रक्षोपाय उपायों की कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है।
- ज. घरेलू उद्योग के रूबरू में आवेदन से प्रश्नावली का उत्तर और अंतिम समायोजन योजना तक समायोजन योजना के संबंध में परिवर्तन हुआ है जो आयातों से प्रतिस्पर्धा के प्रति समारात्मक रूप से समायोजन करने के लिए योजना की कमी को दर्शाता है।
- झ. जांच की शुरुआत में कहीं भी यह नहीं प्रकट किया गया है कि क्या घरेलू उद्योग ने इस तथ्य को दर्शाने के लिए कोई समायोजन योजना प्रस्तुत की है कि किस प्रकार से वे उत्पादकता में वृद्धि, लागत में कमी और सबसे बढ़कर अपनी बिक्री कीमतों में कमी को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए प्राप्त करेंगे।
- ञ. वर्तमान जांच को कोरिया और अन्य देशों के विरुद्ध समानांतर पाटनरोधी जांच की शुरुआत को देखते हुए समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि परस्पर व्यापार जांच की अवधि के साथ उसी उत्पाद के लिए पाटनरोधी शुल्क के साथ-साथ द्विपक्षीय रक्षोपाय शुल्क को उसी समय नहीं लगाया जा सकता है।
- ट. अनंतिम उपायों की सिफारिश 1-3 महीने के भीतर उनकी सिफारिश करने की प्रथा के विरुद्ध काफी समय बीत जाने के बाद की गई थी।
- ठ. सुनवाई के लिए कोई अवसर हितबद्ध पक्षकारों को अनंतिम जांच परिणाम के पहले नहीं दिया गया था और प्रत्येक मुद्दे की जांच नए सिरे से की जानी चाहिए।
- ड. इन आवेदकों द्वारा प्रस्तावित क्षमता विस्तार भावी परिदृश्य हैं जिन्हें कभी भी लागू नहीं किया जाता है और वे इस अनुरोध का खंडन नहीं करते हैं कि प्रयोक्ता मांग-आपूर्ति के कारण आयात करने के लिए बाध्य थे।

३. मांग-आपूर्ति में बहुत अधिक अंतर है और इस कारण से विचाराधीन उत्पाद का आयात भारत में किया जाएगा और घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता का विस्तार नहीं किया है।
४. लगभग दस वर्षों में दो रक्षोपाय उपाय और पाटनरोधी उपाय रहे हैं और आवेदक अपने कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए किसी कार्य-नीति बनाने के बजाए व्यापार उपचारों के माध्यम से आयात प्रतिबंधों पर विश्वास करते हैं।
५. इस उत्पाद को गत वर्षों के लिए संरक्षण दिया गया है और रक्षोपाय उपायों के लिए घरेलू उद्योग को अचानक हानि अथवा कोई आपातकालीन स्थिति के लिए तर्क नहीं हो सकता है।
६. प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा जांच में यह टिप्पणी की थी कि सितंबर, 2017 के अनुसरण में आयातों में वृद्धि मांग-आपूर्ति के अंतर के कारण होगी और इसने सीईपीए के अंतर्गत प्रशुल्क रियायतों पर विचार नहीं किया था।
७. शुल्क लगाने से इन आवेदकों को बाजार में अपने आप के लिए प्रभावी स्थिति सृजित करने और नए प्रवेशार्थियों के लिए बाधाएं उत्पन्न करने की अनुमति मिलेगी।
८. प्राधिकारी ने दूसरी निर्णायक समीक्षा में यह स्वीकार किया कि यदि घरेलू उद्योग ने 100 प्रतिशत संस्थापित क्षमता का उपयोग करने का प्रयास किया भी तब यह घरेलू मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाएगा और सितंबर, 2017 के अनुसरण में आयात मांग-आपूर्ति में अंतर के कारण होगी।
९. प्रारंभिक जांच परिणाम के समय विचार की गई जांच की अवधि को बढ़ाया गया है और उसमें जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में अधिसूचित अवधि से संशोधित किया गया है।

ग. 5. कोरिया से बढ़ा हुआ आयात

12. आवेदकों द्वारा किये गये अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- क. भारत-कोरिया सीईपीए के अनुसरण में, कोरिया के फ्थेलिक एनहाइड्राइड के आयातों पर शुल्क इन वर्षों के दौरान घटाकर शून्य कर दिया गया है।
- ख. आयात की मात्राओं में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों में स्वतंत्र रूप में और उत्पादन, खपत तथा आयातों में हिस्से की तुलना में काफी हद तक वृद्धि हुई है।
- ग. कोरिया से भारत में आयात को भारत-कोरिया सीईपीए के अंतर्गत फ्थेलिक एनहाइड्राइड के लिए शुल्क का लाभ मिलता है। इस कारण से इस देश में अब कोरिया से संबद्ध वस्तुओं का काफी मात्रा में आयात होता है।
- घ. भारत कोरिया के उत्पादकों के लिए एक पसंदीदा बाजार हो गया है क्योंकि कुल निर्यातों में भारत को किए गए निर्यातों के हिस्से में तीन गुना से अधिक वृद्धि हुई है।
- ङ. कोरिया से होने वाले आयातों को अत्यधिक क्षमताओं तथा कम भाड़ा लागत का लाभ मिलता था और अब उसे सीमा शुल्क की रियायतों का भी लाभ मिलता है।
- च. यदि शुल्क रियायतों के कारण कोरिया के आयातों द्वारा कीमत का कोई निर्धारण नहीं होता तब घरेलू उद्योग लाभप्रद कीमतों पर विक्री की होती।
- छ. कोरिया से स्वतंत्र रूप में तथा सापेक्ष रूप में आयात 2019-20 की तीसरी और चौथी तिमाही में भी बहुत अधिक रही है।

13. अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- क. प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रकाशन के लिए कोई नाजुक स्थितियाँ नहीं हैं क्योंकि आयातों में वृद्धि की दर कम हो रही है जबकि अन्य देशों के मामले में इसमें वृद्धि हो रही है।
- ख. रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 3.1 के अनुसार, तर्क संगत और समुचित व्याख्या अवश्य होनी चाहिए जो शुल्क में कटौती और आयातों में कथित वृद्धि के बीच संबंध को दर्शाता हो। प्राधिकारी को एक तर्क संगत व्याख्या और उसके प्रदर्शन की पहचान करनी चाहिए और उसे उपलब्ध कराना चाहिए।

- ग. थार्डलैंड और इंडोनेशिया तथा जिस देश के साथ भारत का एफटीए है, से आयातों में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, ताईवान से आयातों में वृद्धि भी कोरिया से आयातों में वृद्धि के अनुरूप है।
- घ. कोरिया से प्रचलित फ्यैलिक एनहाइड्राइड के आयातों में हाल में, अचानक, तीव्र और बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है।
- ङ. एक अप्रत्याशित घटनाक्रम होना चाहिए जिसके कारण आयातों में वृद्धि होनी चाहिए थी।
- च. आयातों में वृद्धि सीईपीए के अंतर्गत सीमा शुल्क में कटौती के बजाए चीन जन.गण, इंडोनेशिया, इजराइल, रूस, ताईवान, थार्डलैंड और यूएई से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के समय अधिक हुआ है। यह आवेदन आयातों में वृद्धि के लिए एक कारण के रूप में पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के प्रभावों के बारे में मौन है।
- छ. आयातों में 2016-17 से 2017-18 तक की संक्रमण अवधि में इस प्रकार की मात्राओं में वृद्धि नहीं हुई है। आयातों में वृद्धि और प्रशुल्क रियायतों में कोई संसंबंध नहीं है। यह वृद्धि सीईपीए को छोड़कर अन्य कारणों से हुई थी।
- ज. कोरिया से आयात भारत में मांग आपूर्ति में अंतर के अनुपात में हुआ है और इसकी तुलना चीन जन.गण, थार्डलैंड और इंडोनेशिया जैसे आयातों के अन्य प्रमुख स्रोतों से की जा सकती है। यदि शुल्क का समाप्त होना आयातों के लिए कारण होता तब समग्र आयात कोरिया की ओर परिवर्तित हो गया होता।
- झ. मौखिक सुनवाई में आवेदकों ने यह स्वीकार किया कि आयातों के कारण के बारे में कोई निश्चितता नहीं है जो सीईपीए के अंतर्गत शुल्कों की समाप्ति, पाटन अथवा सब्सिडी के कारण भी हो सकती है।
- ञ. तिमाही बार आंकड़ों पर उस अवधि के लिए विचार किया जाना चाहिए था जिसके लिए आयातों में अचानक वृद्धि के होने का दावा घरेलू उद्योग द्वारा किया गया है।
- ट. मांग-आपूर्ति में अंतर को दूर करने के लिए आयात आवश्यक हो गए थे।
- ठ. जबकि कोरिया से आयात भारतीय मांग का लगभग 23 प्रतिशत था, अन्य आयात भारतीय मांग का लगभग 24 प्रतिशत था।
- ड. अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत आयात को कुल आयातों से बाहर रखा ही जाना चाहिए।
- ढ. अर्जेन्टीना फुटवियर और यूएस-स्टील रक्षोपाय में डब्ल्यूटीओ की अपीलीय निकाय के अनुसार, प्राधिकारी को इस अवधि के दौरान आयातों की प्रवृत्ति पर अवश्य विचार करना चाहिए और यह वृद्धि हाल की होनी चाहिए।
- ण. कीमत आधारित क्षति का न होना भी स्पष्ट है क्योंकि घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि यदि पहुंच कीमत को 68.97 प्रति मी.टन जो पहली तिमाही की पहुंच कीमत के समतुल्य है, तक बढ़ा दिया जाता है तब इसे उचित लाभ मिलेगा।
- त. 2019-20 की तीसरी और चौथी तिमाही में आयात की मात्राओं में गिरावट आई और आवेदक के पास अभी भी मांग में 50 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा था।

ग.6. क्षति

14. आवेदकों द्वारा क्षति के संबंध में किए गए अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार हैं:
- क. भारतीय उद्योग के उत्पादन और बिक्री में सबसे हाल की अवधि में काफी हद तक गिरावट आई है। जबकि इस उत्पाद की मांग में वृद्धि नहीं हुई है, आयातों में अचानक वृद्धि हुई है और इस प्रकार से घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा है।
- ख. इस उद्योग की क्षमता उपयोग में 2019-20 की पहली तिमाही में गिरावट आई है।

- ग. उत्पादन और क्षमता के उपयोग में गिरावट से यह स्पष्ट है कि आयातों में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।
- घ. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि इन आयातों के हिस्से में वृद्धि हुई है।
- ड. संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी हद तक कटौती हो रही है। आयात की कीमतों में जांच की अवधि (पीओआई) की पिछली दो तिमाहियों में तेजी से गिरावट आई है। इस प्रकार से यदि आयात बढ़ता रहता है तो घरेलू उद्योग प्रसंस्करण लागत को भी बसूल पाने में भी सक्षम नहीं होगा और उसे बहुत अधिक वित्तीय हानि होगी।
- च. उद्योग का लाभ 2018-19 की दूसरी तिमाही तक बढ़ रहा था। घरेलू उद्योग के लाभ में 2018-19 की दूसरी तिमाही से 2019-20 की पहली तिमाही तक इस अवधि के दौरान बिक्री की हानि पर विचार करते हुए गिरावट आई है।
- छ. भारतीय उद्योग की उत्पादकता में प्रारंभिक रूप से सुधार हुआ लेकिन जांच की अवधि में इसमें काफी हद तक गिरावट आई है।
- ज. पहले हुई गंभीर क्षति के अलावा, आयातों के कारण गंभीर क्षति का खतरा उत्पन्न हो रहा है जो निम्नलिखित से स्पष्ट होगा:
- आयातों की मात्रा में अपेक्षाकृत अल्प अवधि में काफी हद तक वृद्धि हुई है।
 - घरेलू बाजार में बहुत अधिक हिस्सा इन आयातों का बहुत पहले से है और आयातों के हिस्से में वृद्धि हो रही है।
 - घरेलू कीमत और आयात किए गए उत्पाद की कीमत के बीच अंतर बहुत अधिक है।
- झ. बढ़े हुए आयातों को छोड़कर कोई अन्य कारक नहीं है जिनके कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो सकती है।
- ज. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से बहुत कम है।
- ट. घरेलू उद्योग को बिक्री अवसरों तथा सामान्य मार्जिन की हानि हो रही है इसके परिणामस्वरूप बिक्री, लाभ, निवेश पर लाभ और नकद प्रवाह कम कीमत पर आयातों के लगातार मौजूद रहने के कारण कम हो रही है।
- ठ. बढ़े हुए आयातों के फलस्वरूप आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी आई है।
- ड. यह अनुरोध किया जाता है कि कोरिया से आयातों में काफी वृद्धि हुई है जबकि उत्पादन और बिक्री और इसके फलस्वरूप भारतीय उद्योग की क्षमता के उपयोग में काफी हद तक गिरावट आई है।
- ढ. घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री 2019-20 की तिमाही में प्रभावित रही है और घरेलू उद्योग को मार्जिन की हानि होती रही है।
- ण. घरेलू उद्योग के पास बाजार की लगभग 70-80 प्रतिशत को पूरा करने की क्षमता है हालांकि इसका हिस्सा 50-60 प्रतिशत तक ही रह गया है।
- त. भारतीय मांग में अन्य देश के आयात का सामूहिक हिस्सा कोरिया से आयातों की तुलना में कम है।
- थ. घरेलू उद्योग के पास मालसूची 2019-20 की तीसरी और चौथी तिमाही में अपेक्षाकृत अधिक रही है।
- द. 2019-20 की नवीनतम तिमाही में कीमत में कटौती ऐतिहासिक रूप से उच्चतम है।
- ध. घरेलू उद्योग बाजार में अपने उत्पाद के लिए मांग के कारण निर्यात करने के लिए मजबूर हुआ है। ये निर्यात घाटा लगाने वाली कीमतों पर किया गया था।
- न. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, अन्य देशों से आयातों में उस प्रकार से वृद्धि नहीं हुई है जिस प्रकार से मांग में वृद्धि हुई है।

- प. आवेदक आयातों की कम कीमत के लिए इन कारणों की पुष्टि नहीं कर सकते हैं बल्कि आयातों की कम कीमत की जांच के लिए केवल अनुरोध कर सकते हैं।
- फ. पिछली पाटनरोधी जांचों में, यद्यपि आवेदकों का यह विश्वास था कि आयातों को पाटित किया गया था, नकारात्मक पाटन मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कोरिया से आयातों के कारण किया गया था।
- ब. घरेलू उद्योग के निवेश पर लाभ में न केवल कमी आई है बल्कि यह कुछ अवधि में नकारात्मक है।
- भ. यदि घरेलू उद्योग लाभप्रद कीमतों की दर लगाया होता तब कीमत में कटौती अपेक्षाकृत अधिक हुई होती।
- म. घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमताओं पर विगत में लगभग ***करोड़ रु. का निवेश किया है और यह मांग को पूरा करने के लिए अन्य अत्यधिक राशि निवेश कर रहा है।
- य. कोरिया से आयातों की पहुंच कीमत गैर-कोरिया स्रोतों से आयातों की पहुंच कीमत की तुलना में कम है।
- कक. 2016-17 के आंकड़ों के आधार पर पाटनरोधी जांच में परीक्षण की गई क्षति का संदर्भ लेने का कोई औचित्य नहीं है।
- खख. क्षति मार्जिन अथवा कम कीमत पर बिक्री रक्षोपाय नियमावली के अंतर्गत क्षति के निर्धारण का एक संगत मानदंड नहीं है।
- गग. प्रतिवादियों ने 4.5 वर्षों के लिए क्षति संबंधी आंकड़ों की जांच के विरुद्ध ही 2019-20 के पिछले कुछ दिनों के लिए संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है।
- घघ. अन्य देशों में क्षमताएं घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति की जांच के लिए संगत नहीं हैं।
- डड. यूस-स्टील रक्षोपाय जांच में पैनल ने यह माना था कि आयातों के अंतर-प्रवाह और इस प्रकार के अंतर-प्रवाह का घरेलू उद्योग पर क्षतिकारक प्रभावों के प्रकटीकरण के बीच अंतर हो सकता है। इस कारण से यद्यपि इन शुल्कों को पहले कम किया गया था, जब क्षति हुई थी तब अंतर था।
- चच. एशियन पेंट्स की आवश्यकता के कारण आयातों में कोई वृद्धि वर्ष 2017-18 में अपने आप दृष्टिगत हुई होती। हालांकि 2016-17 की तुलना में, आयातों में केवल 4800 मी.ठन तक ही वृद्धि हुई।
- छछ. डाउनस्ट्रीम के उत्पादों के आयातों में वृद्धि का दावा केवल अनुमान है और वे उपचार के लिए प्राधिकारी के पास आने के लिए स्वतंत्र हैं।
- जज. वी कामेश्वर सिंह के मामले में बिहार न्यायालय का निर्णय एआईआर 1952 एससी 252 पूर्ण रूप से यह दर्शाता है कि जनहित जांच की कोई क्षति परिभाषा नहीं होती है और इस कारण से प्रयोक्ता उद्योग पर विचार करते हुए ऐसा किया जाना किसी प्रकार से अपेक्षित नहीं है।
- झझ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने पूर्व की जांच में प्राधिकारी की जांच को गलत तरीके से उद्धृत किया है। जांच का यह आशय था कि मांग-आपूर्ति में अंतर की स्थिति के फलस्वरूप आयात होगा।
15. क्षति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए हैं:
- क. घरेलू उद्योग अपने आप पाटनरोधी जांच के लिए अपनी याचिका में यह मानता है कि इसका कार्यनिष्पादन अच्छा था और यह लाभ में था। इस प्रकार, कोरिया-भारत सीईपीए में दी गई रियायतों के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।
- ख. यह जांच परिणाम सार्थक रूप में इस तथ्य का समाधान नहीं करता है कि क्या कोरिया-भारत सीईपीए के अंतर्गत शुल्कों में कटौती अथवा उसकी समाप्ति के फलस्वरूप ही संबद्ध वस्तु के आयातों में वृद्धि होनी चाहिए जो परिणाम के रूप में घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का वास्तविक कारण होना चाहिए।
- ग. विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि को कोरिया-भारत सीईपीए के अंतर्गत प्रशुल्क रियायतों का कारण नहीं माना जा सकता है बल्कि मांग-आपूर्ति में अंतर, पाटित आयात जिनका निर्धारण पूर्व की जांचों में किया गया है, प्रशुल्क में कटौती और आयातों में वृद्धि के बीच किसी सह-संबंध का न होना आदि जैसे अनेक कारक हैं।

- घ. अप्रैल से सितंबर, 2019 में घरेलू उद्योग के आयातों की पहुंच कीमत और बिक्री कीमत 2017-18 की तुलना में उसी रेंज में है जिसमें नकारात्मक क्षति मार्जिन का निर्धारण किया गया था। इस प्रकार जब घरेलू उद्योग को 2017-18 में क्षति नहीं हो रही थी तब अप्रैल-सितंबर, 2019 की अवधि के लिए घरेलू उद्योग को क्षति का कोई प्रश्न नहीं उठता है।
- ड. घरेलू उद्योग का यह तर्क कि घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कोरिया की पहुंच मूल्य की तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डीजीटीआर की कार्य-पद्धति और गंभीर क्षति के संबंध में न्यायिक समझ के अनुसार नहीं है। “गंभीर क्षति” के निर्धारण में यह आवश्यक है कि एनएसआर के विपरीत घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत (अथवा उचित बिक्री कीमत) से कोरिया से विचाराधीन उत्पाद का पहुंच मूल्य की तुलना की जाए।
- च. आवेदकों ने वर्तमान जांच में क्षति का दावा केवल सीमा शुल्क में कटौती अथवा उसकी समाप्ति के आधार पर किया है जबकि हाल में आरंभ की गई पाटनरोधी जांच में, याचिका में यह दावा किया गया था कि क्षति पाटित आयातों के कारण हुई थी। घरेलू उद्योग प्राधिकारी के समक्ष क्षति के अलग-अलग और परस्पर विरोधी कारण प्रस्तुत कर रहे हैं। अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, केवल आयातों में वृद्धि को घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे का ठोस कारण हो सकता है।
- छ. घरेलू उद्योग के प्रमुख कार्य-निष्पादन संबंधी मानदंडों जैसे क्षमता का उपयोग, उत्पादन, बिक्री, लाभप्रदता किसी क्षति को नहीं दर्शाता है।
- ज. बिक्री कीमत में वृद्धि पहुंच कीमत में वृद्धि से अधिक है।
- झ. आवेदकों ने यह नहीं दर्शाया है कि आयातों में वृद्धि और सीमा शुल्कों में कटौती के कारण कथित क्षति हुई है। यह नहीं दर्शाया गया है कि आयातों में वृद्धि सीमा शुल्कों में कटौती अथवा उसकी समाप्ति के कारण हुई है और केवल वृद्धि भारत-कोरिया सीईपीए के अनुच्छेद 2.22 की आवश्यकता के अनुसार घरेलू उद्योग को क्षति का कारण है।
- ज. आवेदक की वार्षिक रिपोर्टों में चर्चा इस स्थिति में समग्र गिरावट का कोई लक्षण नहीं दर्शाता है।
- ट. आवेदक को प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति की अवधि के लिए आंकड़े उपलब्ध कराना चाहिए। वह अवधि जिसके लिए आवेदन में आंकड़ा उपलब्ध कराया गया है, भासक है।
- ठ. पिछले वर्षों के लिए भी आंकड़ों पर विचार तिमाही आधार पर किया जाना चाहिए था। वार्षिकीकृत आंकड़ों का विश्लेषण रक्षोपाय जांच में व्यवहार्य एवं विश्वसनीय नहीं है जैसाकि डब्ल्यूटीओ के पैनल द्वारा भी भारत-आयरन स्टील प्रोडक्ट्स में माना गया है।
- ड. घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है। यह कद्दे तेल और अन्य पैट्रोकेमिल उत्पादों में उतार-चढ़ाव, सुदूर पूर्व में स्लोडाउन, यूएस-चीन व्यापार प्रतिबंध आदि, मांग को पूरा करने के लिए विस्तार को पूरा करने में विलंब आदि जैसे विभिन्न मुद्दों के बावजूद हुआ है।
- ढ. घरेलू उद्योग की बिक्री में भी 2007-08 की तुलना में नवीनतम अवधि में 38 अंक तक वृद्धि हुई है।
- ण. घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है। क्षमता में उस समय वृद्धि जब घरेलू उद्योग गंभीर क्षति का दावा कर रहा है, को घरेलू उद्योग के क्षति संबंधी दावे को समाप्त करने वाले कारक के रूप में देखा जाना चाहिए।
- त. आवेदकों की उत्पादन विस्तार योजना घरेलू उद्योग के निर्णय का एक लक्षण है कि आने वाले वर्ष में उत्पादन और बिक्री की मात्रा में वृद्धि होगी जो इस बात की गारंटी देता है कि ऐसी कोई गंभीर क्षति नहीं हुई है जिसका दावा घरेलू उद्योग द्वारा किया गया है। वास्तव में एक सकारात्मक दृष्टिकोण है।
- थ. आयात की कीमतों में घरेलू उद्योग की कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति का पालन करते हुए वृद्धि हुई है। आयातों की पहुंच कीमत में सतत तौर पर घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों को कम करने के लिए बाध्य नहीं किया था। इसके विपरीत, निवल बिक्री प्राप्ति अधिक हुई है।

- द. घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने के समय अत्यधिक लाभ अर्जित कर रहा था। वर्तमान लाभ में गिरावट हास नहीं है बल्कि असामान्य रूप से उच्च लाभों में सुधार है।
- ध. हाल में संपन्न पाटनरोधी जांच में, क्षति संबंधी निर्धारण किया गया था और क्षति की संभावना से भी इंकार किया गया था।
- न. कोरिया से आयातों की पहुंच कीमत विभिन्न अन्य स्रोतों से अधिक थी जिसका तात्पर्य यह है कि कोई कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता नहीं थी और सभी निर्यातकों की कुल क्षमता उपयोगिता लगभग 99 प्रतिशत-100 प्रतिशत है जो कोरिया में किसी अत्यधिक अप्रयुक्त क्षमता से इंकार करता है।
- प. जब घरेलू उद्योग सीईपीए के अनुसार गंभीर क्षति को स्थापित करने में सक्षम नहीं हो पाया है तब गंभीर क्षति के खतरे के दावे को बहुत सावधानी से लिया जाना चाहिए।
- फ. कीमत में कटौती शुल्कों को समाप्त किए जाने के बाद कम हुई है जो यह दर्शाता है कि इसके फलस्वरूप पहुंच कीमतों में कमी नहीं आई। घरेलू उद्योग की कीमतें बहुत अधिक हैं और लाभप्रद स्तरों पर हैं जो सकारात्मक कटौती के लिए कारण है।
- ब. जबकि निवेश पर लाभ में कमी आई है, यह कुछ ऐतिहासिक अवधि से बहुत अच्छा है जिसमें आवेदकों को नकारात्मक लाभ हुआ था।
- भ. महानिदेशालय ने प्रारंभिक जांच परिणाम में विशिष्ट निष्कर्ष निकालने के लिए अनंतिम जांच परिणामों के समय विचार की गई जांच की अवधि में संशोधन किया है जो अन्य प्रकार से संभव नहीं हुआ होता। प्रारंभिक जांच परिणामों के लिए विचार की गई अवधि यह दर्शाती है कि वह अवधि जिसके लिए क्षति का दावा किया गया है, शुल्क की कटौती अथवा उसकी समाप्ति की अवधि के अग्रानुक्रम में नहीं है।
- म. घरेलू उद्योग ने केवल एक तिमाही तक के घाटा उठाने वाली निर्यात बिक्री के लिए अपने तर्कों को सीमित रखा है जिसका आशय यह है कि इसे अन्य 17 तिमाहियों में हानि पहुंचाने वाले निर्यातों के कारण घाटा नहीं हुआ था।
- य. घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली छमाही से हाल की गिरावट का उल्लेख सीईपीए के अंतर्गत शुल्कों में कटौती अथवा उसकी समाप्ति के समय नहीं की गई है।
- कक. घरेलू उद्योग शुल्कों की समाप्ति के तत्काल बाद की अवधि में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था क्योंकि निवेश पर लाभ ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर पहुंच गया।
- खख. कोरिया से आयातों की पहुंच कीमत कोरिया से आयातों के मामले में भी किसी कीमत संबंधी क्षति को इंकार करते हुए आयातों से अधिकांश अन्य स्रोतों की तुलना में अधिक रही है।
- गग. अन्य देशों से आयातों में कोरिया से आयातों की तुलना में पहुंच कीमत में उच्चतर गिरावट दर्ज की।
- घघ. भारत में इस उत्पाद की कीमत आयातों की पहुंच कीमत से पाटित नहीं हुई थी। बिक्री कीमत और पहुंच कीमत के बीच अंतर घरेलू उद्योग द्वारा वसूले गए उच्च कीमत के कारण हो सकती है।
- डड. सीईपीए और इस नियमावली के अनुसार गंभीर क्षति का अर्थ घरेलू उद्योग की स्थिति में बहुत अधिक समग्र हानि है।
- चच. न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया से फ्रैश, चिल्ड अथवा फ्रोजन लैम्ब मीट के आयातों पर संयुक्त राज्य - रक्षोपाय उपायों में डब्ल्यूटीओ की अपीलीय निकाय के अनुसार, गंभीर शब्द का अर्थ क्षति का बहुत उच्च मानदंड है। गंभीर क्षति और क्षति के खतरे के लिए यूस लैम्ब मामले में उसी दृष्टिकोण को अपनाया गया था।
- छछ. वार्षिकीकृत आंकड़ों की तुलना के लिए कोई कारण उपलब्ध नहीं कराया गया है। यदि कारण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तब तुलना वस्तुपरक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराता है।
- जज. प्रारंभिक जांच परिणाम 2019-20 की दूसरी तिमाही के लिए आंकड़ों पर आधारित है जो यह निर्धारित करता है कि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट आई है।

- झज्ज. घरेलू उद्योग शुल्कों की समाप्ति के तत्काल बाद की अवधि में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और इसे उस वर्ष में जिसमें शुल्कों को समाप्त किया गया था निवेश पर 50-60 प्रतिशत लाभ मिला।
- जज. घरेलू उद्योग ने स्वीकार्य तौर पर 2019-20 की पहली तिमाही तक लाभ में था, जैसा कि पाटन मार्जिन याचिका में उल्लेख किया गया है। तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही के आंकड़ों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे जांच की अवधि का भाग नहीं है और जिसके लिए समानांतर आवेदन पाटनरोधी शुल्क के लिए दायर किया गया है जहां घरेलू उद्योग ने यह आरोप लगाया है कि क्षति का एकमात्र कारण पाटन है।
- टट. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को क्षति का आंकलन करने के लिए आयातों और घरेलू उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों की जांच करनी चाहिये।
- ठठ. आवेदक जांच के ऐसे विलंबित चरण में 2019-20 की तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही के लिए आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।
- डड. शुल्कों की समाप्ति के बाद कीमत में कटौती कम हुई जो अकेला यह दर्शाता है कि अपने आप में शुल्कों की समाप्ति के कारण पहुंच कीमत में कोई कटौती नहीं हुई जिसके फलस्वरूप कीमत में उच्चतर कटौती हुई।

ग.7. कारणात्मक संबंध

16. आवेदकों द्वारा कारणात्मक संबंध के बारे में किए गए अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार हैं:

- क. मांग-आपूर्ति के अंतर की स्थिति में, आयात होता है। हालांकि कोरिया से आयातों में वृद्धि मांग में वृद्धि के अनुपात में नहीं है जिसकी पुष्टि इस तथ्य से हो जाती है कि अन्य देशों से आयातों में पिछले दो वर्षों में गिरावट आई है।
- ख. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा संबद्ध देश से आयातों के कारण को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।
- ग. कीमतों की बेंच मार्किंग का आशय केवल यह है कि कोरिया की कीमतें अन्य प्रतियोगियों के लिए कीमतों का एक मानदंड के रूप में कार्य करता है जो अन्य देशों से आयातों की कम कीमत का कारण है।
- घ. घरेलू उद्योग ने कभी भी अपने ग्राहकों को यह नहीं सूचित किया है कि यह उत्पादन संबंधी मुद्दों का सामना कर रहा है। उपभोक्ताओं को तथ्यों को दर्शाने के लिए बुलाया जा सकता है। पुनर्गठन की प्रक्रिया तब की गई थी जब इस संयंत्र के अधिकांश हिस्से चालू थे।
- ड. कच्चे तेल की कीमतों में उत्तर-चढ़ाव का सामना न केवल घरेलू उद्योग द्वारा किया गया था बल्कि वैश्विक स्तर पर सभी उत्पादकों द्वारा किया गया था। कोरिया से आयातों के कारण घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को कच्चे तेल की कीमतों के अनुरूप नहीं कर सका।
- च. यदि आयातों में वृद्धि शुल्कों को समाप्त किए जाने के कारण हुई होती तब आयातों में ताइवान और इजरायल से भी बढ़ोतरी हुई होती। कोरिया के प्रमुख उत्पादक को शून्य पाटनरोधी शुल्क का लाभ मिला और इस कारण से शुल्कों की समाप्ति से आयातों में वृद्धि को जोड़ने का कोई कारण नहीं है।
- छ. घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन कच्चे माल की उपलब्धता और आयातों से प्रतिस्पर्धा पर ही निर्भर है।
- ज. प्रतिकूल दावे आर्थोजाइलिन के संबंध में किया गया है। जबकि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को अपनी आपूर्ति के संबंध में मुद्दों का सामना करना पड़ा, अन्य ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को बहुत आपूर्ति का लाभ मिलता है।
- झ. यूस-व्हीट ग्लेन में अपीलीय निकाय का यह मत था कि बढ़ा हुआ आयात क्षति के कारणों में से और क्षति के लिए एकमात्र कारण नहीं हो सकता है और प्राधिकारी को केवल इस तथ्य का आकलन करने की आवश्यकता है कि क्या बढ़े हुए आयातों और गंभीर क्षति के बीच “कारण और प्रभाव का ठोस संबंध” है।

17. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कारणात्मक संबंध के बारे में किए गए अनुरोध नीचे दिए गए हैं:

- क. योजनाबद्ध क्षमता विस्तार में विलंब, योजनाबद्ध अल्पकालीन सटडाउन, आर्थोडाइलिन कीमतों में उतार चढ़ाव भी आवेदकों के कार्य-निष्पादन को प्रभावित किया होगा।
- ख. कच्चे माल की कीमतों और अंतिम उत्पाद की कीमतों में कम होता हुआ अंतर घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन को प्रभावित करता है।
- ग. पाटनरोधी जांच में, क्षति का कारण कोरिया सहित चार देशों से पाठन है। सीमा शुल्कों में कटौती/उसकी समाप्ति के कारण आयात का ऐसी क्षति को कारण बताने की व्याख्या अंतिम जांच परिणामों में नहीं की गई है।
- घ. संबद्ध आयातों की तुलना में आशियान देशों से आयातों में अपेक्षाकृत अधिक तीव्र वृद्धि हुई है। इस कारण से केवल गंभीर क्षति को केवल संबद्ध आयातों का कारण नहीं ठहराया जा सकता है।
- ड. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री पर योजनाबद्ध सटडाउन और अनुरक्षण, पुरानी प्रौद्योगिकी, फ्लैश स्टोर्म्स और बाद के कारण पड़ा था। इन तथ्यों को मान लिया गया है कि अन्य कारणों से क्षति होती है।
- च. बाजार की रिपोर्ट यह संकेत देती है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए आयात की कीमतें गंभीर वैश्विक अर्थव्यवस्था के बाद हाल में बहुत तेजी से गिरा है और कच्चे माल के भविष्य को चकनाचूर कर दिया है। 20 मार्च, 2020 को औसत भारतीय कीमत 720 डॉलर प्रति टन थी जो उस कीमत से 100 डालर प्रति टन कम है जो महीने के शुरू में थी।
- छ. प्रारंभिक जांच परिणाम में डीजीटीआर क्षति पहुंचाने वाले अन्य कारकों के संबंध में सुग्राह्य वैकल्पिक स्पष्टीकरण का उचित रूप से मूल्यांकन करने और आंकलन करने में असफल रहा है।
- ज. प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे विभिन्न कारकों के प्रभावों के बीच अंतर करें और उसके बाद बढ़े हुए आयातों के कारण हुई क्षति कारक प्रभावों का कारण स्थापित करें।
- झ. घरेलू बिक्री में गिरावट का कारण कैप्टिव खपत में वृद्धि हो सकती है।
- ञ. आवेदकों ने सितंबर, 2017 की अवधि तक क्षति के कारण के रूप में पाठन का दावा किया है।
- ट. घरेलू उद्योग का उत्पादन भारत में ओर्थोजाइलिन की आपूर्ति में कमी के कारण प्रभावित हुआ होगा।
- ठ. आवेदकों ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह माना है कि कार्य-निष्पादन की गिरावट का कारण कच्चे माल और ओएक्स की कीमत में उतार-चढ़ाव और वैश्विक व्यापार परिवेश में चुनौतियों, ईस्ट स्लोडाउन, उत्पाद की कीमतों में नर्मी आना और डाऊनस्ट्रीम उद्योगों द्वारा भंडार खाली करना था। इस प्रकार के विस्तार के कारण मार्जिन में सुधार को सीईपीए के अंतर्गत शुल्कों की समाप्ति को नहीं माना जाना चाहिए।
- ड. यदि आयातों में वृद्धि सीमा शुल्क के समाप्त होने के कारण हुई थी तब वर्ष 2017-18 से यह वृद्धि वृष्टिगत हुई होती। घरेलू उद्योग को 2018-19 तक क्षति नहीं हो रही थी। आयातों में वृद्धि कोरिया, ताइवान और इजरायल से आयातों के पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से अधिक संबंधित था।
- ढ. पुनर्गठन की प्रक्रिया और आवेदकों के अन्य आंतरिक कारणों से आपूर्ति में बाधा आई थी जिसने प्रयोक्ताओं को आयात करने के लिए बाध्य कर दिया क्योंकि आपूर्ति का कोई अन्य स्रोत नहीं था।
- ण. टीसीएल का सीईओ ने अपने एक भाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि कमतर उत्पादन और उच्चतर लागत थी क्योंकि प्रमुख पुनर्गठन परियोजना जारी थी।
- त. अगस्त, 2019 में आईजीपीएल के निवेशक की प्रस्तुति के अनुसार, आयातों में उच्च घरेलू मांग के आधार पर पिछले तीन वर्षों में वृद्धि हुई है।
- थ. एशियन पेंट्स संयंत्र के बंद होने के प्रभाव ने उत्पादन में गिरावट और आयातों में वृद्धि और न कि सीमा शुल्क में कटौती को प्रभावित किया है।

- द. घरेलू उद्योग के उत्पादन में कच्चे तेल और अन्य पेट्रोकेमिकल उत्पादों में उतार-चढ़ाव, सुदूर पूर्व में सटडाउन, यूस-चीन व्यापार प्रतिबंध आदि, मांग को पूरा करने के लिए विस्तार योजनाओं को पूरा करने में विलंब जैसे विभिन्न मुद्दों के बावजूद नवीनतम अवधि में 13 अंकों तक वृद्धि हुई है।

ग.8 जनहित

18. आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए हैं:

- क. द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय कोरिया अथवा किसी अन्य देश से आयातों को नहीं रोकेगा और इस कारण से कोई कमी नहीं होगी।
- ख. घरेलू उद्योग के लिए यह अपेक्षित होगा कि वे परस्पर प्रतिस्पर्धा करें और बाजार में कोई एकाधिकार नहीं बन पाएगा।
- ग. विगत में अनेक व्यापार उपचारात्मक जांच हुई हैं लेकिन प्रयोक्ता कभी भी उन पर शुल्कों के प्रतिकूल प्रभाव की पुष्टि करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं।
- घ. जनहित जांच को भी घरेलू उद्योग पर विचार करने की आवश्यकता है।
- ड. इस दावे के विपरीत कि संबद्ध वस्तु केवल मध्यवर्ती उत्पाद हैं, एक पूर्ण रूप से स्वस्थ मध्यवर्ती उद्योग प्रयोक्ता उद्योगों के विकास के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है।

19. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए हैं:

- क. रक्षोपाय उपाय लगाने से डाउनस्ट्रीम विकास को गंभीर रूप से क्षति पहुंचेगी और स्वयं घरेलू उद्योग की संभावनाएं प्रभावित होगी।
- ख. शुल्कों को लगाना जनहित के विरुद्ध होगा क्योंकि मांग और आपूर्ति में अंतर है तथा इन वस्तुओं का उपयोग विभिन्न उत्पादों के उत्पादन में रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में किया जाता है।
- ग. जनहित जांच को केवल घरेलू उद्योग तक सीमित नहीं रखा जा सकता है बल्कि अपेक्षाकृत बड़े उद्योग के हितों पर विचार करने की आवश्यकता है।
- घ. इस शुल्क को लगाने के फलस्वरूप आयात किए गए उत्पाद की कीमत में वृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप अंततोगत्वा स्थानीय उत्पादकों द्वारा कीमतों में वृद्धि की जाएगी।
- ड. पैन उपभोक्ता मद नहीं है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के मूल्यवर्धित उत्पादों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। लोकल के लिए वोकल अभियान को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि पैथेलेट प्लास्टिसाइजर्स जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए और न कि उस पर अत्यधिक करों का बोझ डाला जाए।
- च. पैथेलिक एनहाइड्राइड पर रक्षोपाय शुल्क लगाने से पैथेलेट प्लास्टिसाइजर्स के आयातों के लिए बहुत बड़ा द्वारा खुल जाएगा जो तेल की कीमतों में किसी वृद्धि को बनाए रखने की स्थिति में नहीं है। पैथेलेट प्लास्टिसाइजर्स का भी वर्तमान में विभिन्न एफटीए के अंतर्गत शून्य मूल सीमा शुल्क के साथ भारत में आयात किया जा रहा है।
- छ. कच्चे माल अर्थात् पैन और ओक्सो एल्कोहल को पैथेलेट प्लास्टिसाइजर्स में परिवर्तित करने में मूल्यवर्धन यूएस डॉलर 50 प्रति टन तक कम है और कच्चे माल की कीमत में किसी वृद्धि से आयात किए गए पैथेलेट प्लास्टिसाइजर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाएगा।

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच

20. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने अनुरोधों में उपलब्ध कराई गई सूचना पर प्राधिकारी द्वारा वर्तमान निर्धारण के उद्देश्य से विचार किया गया है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अलग-अलग हितबद्ध पक्षकारों ने एक ही तर्क यद्यपि अलग-अलग तरीके से और अलग-अलग भाषा में दिए हैं। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच परिणाम में इन अनुरोधों की जांच की है और उसका समाधान किया है। संबद्ध आयातों में वृद्धि, गंभीर क्षति और कारणात्मक

संबंध के संबंध में इसमें नीचे दी गई जांच वास्तव में आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर विचार करता है।

- क. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच और प्रस्तावित उपाय के उद्देश्य पर सही परिपेक्ष्य में विचार किया जाना अपेक्षित है। कोरिया से आयातों को व्यापार करार के अंतर्गत चरणबद्ध रूप में पूर्व में रियायत दी गई थी। व्यापार करार में रक्षोपाय उपाय लगाना और करार में उल्लिखित कुछ शर्तों के अंतर्गत शुल्क रियायत वापस लेने का प्रावधान है। इस प्रकार से, वर्तमान जांच का उद्देश्य कोरिया से हुए आयातों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाना है। यह उद्देश्य केवल इस तथ्य पर विचार करेगा कि क्या पूर्व में दी गई रियायत को वापस लिए जाने की आवश्यकता है या नहीं। इसके अलावा, रियायत को वापस लिए जाने से या तो कोरिया अथवा अन्य देशों से भारत में आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होगा अथवा उस पर रोक नहीं लगेगी।
- ख. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां इस उत्पाद की मांग देश में उपलब्ध क्षमताओं से अधिक हो, आयात अपरिहार्य है। वर्तमान जांच का उद्देश्य आयातों को प्रतिबंधित करने का नहीं है। हालांकि ऐसी स्थिति में जहां उत्पाद की मांग भारत में क्षमताओं से अधिक है और इस देश में बहुत अधिक मात्रा में आयात हुए हैं, घरेलू उद्योग की कीमतों पर आयातों की पहुंच कीमत का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से यह अपने आप में आयात की मात्रा नहीं है बल्कि आयातों की कीमत है जो घरेलू उद्योग की चिंता की बात है। तथ्य यह है कि कुल मिलाकर कोरिया से हुए आयातों की पहुंच कीमत गैर-कोरियाई आयातों की पहुंच कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम हो गई। इस प्रकार से घरेलू उद्योग कोरियाई कीमतों के अनुरूप अपनी कीमत रखने के लिए बाध्य हो गया है और यह कच्चे माल की कीमतों में हुए परिवर्तनों के अनुरूप पूर्ण रूप से अपनी कीमतों को निर्धारित करने में सक्षम नहीं हो पाया था जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हुई।
- ग. इस तर्क के संबंध में कि कोरिया-भारत सीईपीए के अंतर्गत शुल्कों में कटौती अथवा उसकी समाप्ति मात्र के फलस्वरूप संबद्ध वस्तुओं के आयातों में वृद्धि होनी चाहिए जो बाद में घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का वास्तविक कारण होना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विभिन्न कानूनों के अंतर्गत कानूनी प्रावधान की इस उद्देश्य से तथा सामंजस्य रूप से इन विनियमों द्वारा प्राप्त किए गए उद्देश्य के संबंध में व्याख्या किया जाना अपेक्षित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चाहे यह पाटन अथवा सब्सिडी अथवा प्रशुल्क रियायतें हैं, इनका प्रभाव घरेलू उद्योग द्वारा आयातों की कमतर कीमत के रूप में महसूस किया जाता है। शुल्क रियायतों अथवा पाटित या सब्सिडीयुक्त आयातों के फलस्वरूप अंततः आयातों की सीआईएफ कीमत और उसके परिणामस्वरूप आयातों की पहुंच कीमत में कमी होगी। अंततः यह आयातों की पहुंच कीमत है जो घरेलू उद्योग की घरेलू कीमत से प्रतिस्पर्धा करता है। इस प्रकार से कारणात्मक संबंध के विचारार्थ संगत कारक यह है कि क्या संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत क्षति का कारण है अथवा क्या घरेलू उद्योग को पहुंच कीमत संबद्ध देशों की कम की गई कीमत को छोड़कर अन्य कारणों से हुई है। इसके अलावा, उस स्थिति में जब यह भी संभव हो कि घरेलू उद्योग को न केवल आयातों की कम की गई पहुंच कीमत के कारण बल्कि अन्य कारकों जैसे संयंत्र का बंद होना, लाकडाउन, प्रमुख अनुरक्षण, आग, बाढ़, कच्चे माल की कमी आदि के कारण भी होती है। इस प्रकार से, इस कानून में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति का वास्तविक कारण आयातों की कम की गई पहुंच कीमत अथवा कुछ अन्य कारक हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों की कीमत में कटौती शुल्क रियायतों अथवा पाटन अथवा सब्सिडी अथवा इन सभी या इनमें से कुछ के सम्मिश्रण के कारण हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में घरेलू उद्योग को यह अधिकार प्राप्त है कि वे इन सभी कानूनों के एक ही समय में उपयोग के माध्यम से अपने आप के लिए संरक्षण प्राप्त करें। इन स्थितियों में, एकमात्र प्रतिबंध यह है कि घरेलू उद्योग उसी क्षति के लिए दोहरे उपचार की मांग नहीं कर सकता है। हालांकि, इसका उपयुक्त रूप से समाधान घरेलू उद्योग को उपचार की अनुमति देते समय किया जा सकता है। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि यह तथ्य कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण क्षति हो सकती थी, का आशय यह नहीं है कि घरेलू उद्योग को प्रशुल्क रियायतों के कारण क्षति नहीं हुई है।

- घ. इसके अलावा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि न तो व्यापार करार और न ही वर्तमान नियमावली में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग को क्षति का एकमात्र कारण शुल्क रियायत होना चाहिए। सीईपीए में यह प्रावधान है कि केवल बढ़े हुए आयात समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तु का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अथवा उससे खतरे का वास्तविक कारण होना चाहिए। इसके अलावा, इस करार में प्रावधान है कि इस तथ्य का निर्धारण कि मूल वस्तु का आयात इस करार के अंतर्गत प्रावधान की गई सीमा शुल्क में कटौती अथवा उसकी समाप्ति के फलस्वरूप ही होना चाहिए यदि इस प्रकार की कटौती अथवा उसकी समाप्ति यह कारण है जो आयातों में वृद्धि को वास्तविक रूप में निर्धारित करता है बल्कि वह स्थिति अन्य कारण के समान अथवा उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, करार में यह भी प्रावधान है कि इस प्रकार की कटौती अथवा निर्धारण जिसका उल्लेख करार में किया गया है, के पूर्व अपने आप ऐसी कमी के आरंभ होने अथवा उसकी समाप्ति के बीच समयावधि के बीतने के साथ नहीं होगा। यह स्पष्ट रूप से इस अर्थ से है कि बड़ा हुआ आयात क्षति का एकमात्र कारण नहीं हो सकता है। केवल बढ़े हुए आयात क्षति का वास्तविक कारण होना चाहिए। पाटनरोधी शुल्क नियमावली में भी यह प्रावधान नहीं है कि पाटन घरेलू उद्योग को क्षति का एकमात्र कारण नहीं होना चाहिए। वर्तमान मामले में उदाहरण के लिए, घरेलू उद्योग को क्षति पाटन और शुल्क रियायतों दोनों के कारण हो सकती है। यह बिल्कुल संभव है कि जबकि कुछ विदेशी उत्पादकों ने पाटन का सहारा लिया, कुछ ने नहीं लिया तब भी उनमें से सभी को सीमा शुल्क के समान स्तर का सामना करना पड़ा। वास्तव में प्राधिकारी ने पाटनरोधी जांच के दौरान यह पाया था कि पाटन की मात्रा अलग-अलग विदेशी उत्पादकों के मामले में वास्तविक रूप से अलग-अलग हैं।
- ड. इसके अलावा यह नोट किया जाता है कि इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या और किस सीमा तक शुल्क रियायतों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, प्राधिकारी ने प्रशुल्क में कटौती/उसकी समाप्ति की अवधि के दौरान तथा प्रशुल्क की समाप्ति के बाद की अवधि के दौरान शुल्क रियायत अवधि के पूर्व घरेलू उद्योग को आयात की मात्रा और कार्य-निष्पादन पर विचार कर अपेक्षाकृत अधिक लम्बी अवधि के लिए इन आंकड़ों पर अतिरिक्त रूप से विचार किया है। नीचे दी गई तालिका वास्तविक स्थिति को दर्शाती है। सीमा प्रशुल्क की समाप्ति के बाद स्वतंत्र रूप में तथा उत्पादन और खपत दोनों की तुलना में आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। जबकि कीमत में कटौती पूर्व में नकारात्मक थी, वह प्रगामी रूप से सकारात्मक हो गई है क्योंकि शुल्क रियायत में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में इस अवधि के दौरान बाजार हिस्से और लाभ के मामले में गिरावट आई है। इसके अलावा, सबसे हाल की अवधि में, आयातों में और अधिक वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में उत्पादन, क्षमता का उपयोग, घरेलू बिक्री की मात्रा और लाभ/हानि में गिरावट आई है। इस प्रकार से घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन ने कोरिया से आयात होने का प्राथमिक कारण में गिरावट दर्शाई है।

वर्ष	कोरिया से आयात	उत्पादन	विक्री	बाजार हिस्सा	लाभ/हानि	आरओआई	कीमत में कटौती
				घरेलू उद्योग	कोरिया		
	मी.टन	मी.टन-प्रवृत्ति	मी.टन	% रेंज	%	लाख रु.-प्रवृत्ति	% - प्रवृत्ति
2007-08	14,015	100	100	70-80%	7%	100	100
(10-0)							
2008-09	13,938	85	97	70-80%	7%	-142	-46
(10-0)							
2009-10	11,420	94	130	70-80%	5%	68	74
(10-0)							
2010-11	28,073	94	131	60-70%	10%	7	31
0-10							

2011-12	16,183	95	128	65-75%	6%	-31	44	0-10
2012-13	14,409	97	138	60-70%	5%	35	87	0-10
2013-14	18,599	101	137	60-70%	7%	-137	-3	(10-0)
2014-15	15,124	118	158	70-80%	5%	-76	40	(20-10)
2015-16	25,252	124	156	60-70%	8%	132	122	0-10
2016-17	33,766	120	153	60-70%	10%	377	248	5-15
2017-18	41,664	124	160	55-65%	11%	770	353	0-10
2018-19	49,081	120	162	50-60%	13%	537	257	0-10
2019-20 की पहली तिमाही	22,819	113	138	45-55%	23%	34	61	5-15
2019-20 की दूसरी तिमाही	26,007	108	150	45-55%	25%	-4	9	0-10

- च. इस तर्के के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराया गया आंकड़ा उस अवधि से सबंधित नहीं है जिसकी पहचान जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में किया गया है, यह नोट किया जाता है कि इस आवेदन में अप्रैल 2007 से जून, 2019 की अवधि के आंकड़े हैं। इसके अलावा, जबकि जांच के आरंभ का उत्तर देते हुए आवेदकों ने सितंबर, 2019 तक की अवधि के लिए आंकड़े उपलब्ध कराएं हैं। इस प्रकार से हितबद्ध पक्षकारों को उक्त अवधि के लिए सूचना पर टिप्पणी करने के लिए संगत सूचना और अवसर मिला है। इस कारण से प्राधिकारी ने बढ़े हुए आयातों और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की जांच करने के उद्देश्य से अप्रैल, 2015 से सितंबर, 2019 तक की अवधि पर विचार किया है। हालांकि, चूंकि हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या आयातों में वृद्धि इस करार के अंतर्गत प्रशुल्क रियायतों के परिणाम के तौर पर हुआ है और इसके परिणामस्वरूप क्षति हो रही है, प्राधिकारी ने अतिरिक्त रूप से इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए अप्रैल 2007 से जून, 2019 तक की अवधि के लिए आवेदन में निहित सूचना पर अतिरिक्त रूप से विचार किया है कि क्या प्रशुल्क में रियायत के फलस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई है। जुलाई-सितंबर, 2019 की अवधि को भी इस तथ्य पर विचार करते हुए जोड़ा गया है कि यह एक रक्षोपाय जांच है और प्राधिकारी ने विगत में बाद की अवधि के आरंभ होने के बाद की अवधि के आंकड़े जोड़े हैं। हालांकि, जांच की शुरुआत की तिथि पर विचार करते हुए, बाद की अवधि (अक्टूबर, 2019-20) के लिए आंकड़ों पर विचार वर्तमान उद्देश्यों से नहीं किया गया है।
- छ. इस अनुरोध के संबंध में कि समायोजन योजना को आवेदन के साथ मूल रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया था और इस कारण से जांच की शुरुआत कानून की दृष्टि से गलत है, यह नोट किया जाता है कि आवेदन में समायोजन योजना की आवश्यकता जांच की शुरुआत की आवश्यकता के संबंध में निर्णय लेने के उद्देश्य से नहीं है। जांच के आरंभ होने के चरण में, केवल ऐसी सूचना जो जांच के आरंभन के लिए संगत है, पर विचार किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार से जबकि नियम 4(2)(ख) में समायोजन योजना के संबंध में सूचना का प्रावधान है, इसमें प्राधिकारी से यह अपेक्षित नहीं है कि वे जांच की शुरुआत करने के पूर्व समायोजन योजना पर विचार करें। जब भी आवेदन के प्रोफार्मा में समायोजन योजना के संबंध में सूचना का प्रावधान है, यह नोट किया जाता है कि उक्त सूचना की जांच के आरंभन के चरण में कोई उपयोगिता नहीं है। वास्तव में, प्राधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए भी शुल्क पर विचार कर सकते थे जिसमें

समायोजन योजना के संबंध में सूचना असंगत हुई होती। इसस प्रकार से, समायोजन योजना के संबंध में सूचना जांच के आरंभन के संबंध में निर्णय के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। उक्त सूचना नियम 10 के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार अंतिम निर्धारण के समय और न कि जांच की शुरुआत के चरण में शुल्क की अवधि के लिए संगत है। किसी भी मामले में घरेलू उद्योग ने जांच की शुरुआत के बाद समायोजन योजना नहीं दी है।

- ज. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने पहले एक समायोजन योजना बनाई थी जिसे घरेलू उद्योग ने कभी भी कार्यान्वित नहीं किया, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में, घरेलू उद्योग ने ***करोड़ रु. का निवेश किया है जिसमें से घरेलू उद्योग ने ***करोड़ रु की राशि पहले ही खर्च कर दी है और इसमें ** करोड़ रु. की राशि के प्रति वचनबद्धता दर्शाई है। इस प्रकार से यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि घरेलू उद्योग ने अपने आप को समायोजित करने के लिए कोई उपाय नहीं किए हैं।
- झ. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय) नियमावली, 2017 के साथ पठित भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी करार के अंतर्गत शुरु की गई एक द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच है। प्राधिकारी ने इस तथ्य की भी जांच की है कि क्या इस करार के अंतर्गत प्रशुल्क रियायतों के परिणामस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई है अथवा नहीं। इस उद्देश्य से प्राधिकारी ने अप्रैल, 2007 से सितंबर, 2019 तक इस उत्पाद के आयातों पर विचार किया है। यह नोट किया जाता है कि 2015-16 से आयातों की मात्रा में स्वतंत्र रूप में तथा उत्पादन और खपत की तुलना में वृद्धि हुई है क्योंकि प्रशुल्कों की रियायतों में वृद्धि हुई।
- ज. इसके अलावा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि शुल्क पूर्व रियायत को शामिल करते हुए अपेक्षाकृत अधिक लंबी अवधि के दौरान आयातों पर विचार करना, शुल्क की समाप्ति के बाद की अवधि और शुल्क रियायत स्पष्ट रूप से आयातों में अचानक बहुत अधिक वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा, सबसे अधिक हाल की अवधि में आयात पर विचार आयात में अचानक वृद्धि को दर्शाता है।
- ट. गैर-संबद्ध देशों से आयातों के संबंध में, यह देखा गया है कि आयात शुल्कों की पहुंच कीमत कोरिया से आयातों की पहुंच कीमत की तुलना में गैर-संबद्ध देशों से अधिक है। इसके अलावा, प्रत्येक अन्य देशों से अलग-अलग आयातों की मात्रा कोरिया से आयातों की मात्रा से बहुत कम है।
- ठ. आशियान देशों से आयातों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि आशियान देशों से आयात की मात्रा स्वतंत्र रूप में तथा भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में कोरिया से आयातों की मात्रा से बहुत कम है। इसके अलावा, आशियान देशों से आयातों में वृद्धि कोरिया से आयातों में वृद्धि से बहुत कम है।
- ड. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने के कारण आयातों में वृद्धि हुई है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह तथ्य को सिद्ध नहीं करता है कि कोरिया से आयातों के कारण क्षति नहीं हुई है।
- ढ. इस तर्क के संबंध में कि आयातों में मांग-आपूर्ति में अंतर के कारण वृद्धि हुई, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग-आपूर्ति में अंतर अपने आप में आयात को न्यायोचित ठहराते हैं। हालांकि, कोरिया से आयातों की पहुंच कीमत न केवल घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत बल्कि अनेक देशों से आयात की कीमत से भी कम है। इसके अलावा, अनेक देश भारतीय बाजार में इस उत्पाद की आपूर्ति करते रहे हैं। हालांकि कोरिया से आयात का हिस्सा का कोरिया से हुए आयातों के द्वारा प्राप्त प्रमुख स्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग को संगत अवधि के दौरान उत्पादन और घरेलू बिक्री में गिरावट का सामना करना पड़ा है। घरेलू उद्योग के पास मालसूची में वृद्धि हुई है। ये तथ्य दर्शाते हैं कि जबकि आयातों की मात्रा मांग-आपूर्ति में अंतर के कारण हुई है, ये आयात उस कीमत पर हुए हैं जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई।

- ए. इस तर्क के संबंध में कि अग्रिम अधिकरण योजना के अंतर्गत बहुत अधिक आयात हुआ है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि आयात इस करार के अंतर्गत शून्य शुल्क के अधीन हैं अतः यह उस तर्क का उल्लंघन करता है कि क्यों कोई हितबद्ध पक्षकार कोरिया से अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत आयात करेगा और निर्यात दायित्व अपने ऊपर लेगा जब बिना किसी निर्यात दायित्व को अपने ऊपर लिए बिना शुल्क छूट की वही राशि उपलब्ध है। आयातों/उपभोक्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना यह नहीं दर्शाती है कि कोरिया से बहुत अधिक मात्रा में आयात अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत हुए हैं।
- त. याचिकाकर्ता कंपनियों का प्रकाशित बिना लेखा परीक्षा के तिमाही परिणाम भी यह दर्शाते हैं कि लाभ में बहुत अधिक गिरावट आई है और इस निष्कर्ष का खंडन नहीं करते हैं कि घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोरिया से आयातों का प्रभाव पड़ा था।
- थ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह सिद्ध नहीं किया गया है कि किस प्रकार क्षमता का पुनर्गठन, क्षमता का योजनाबद्ध विस्तार में विलंब, योजनाबद्ध अल्पकालीन सटडाउन आदि घरेलू उद्योग को अपने उत्पाद की कीमत निर्धारित करने अथवा अपने उत्पादन की बिक्री करने में क्षति का प्रमुख कारण था। घरेलू उद्योग को क्षति प्राथमिक रूप से घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त की गई कीमत और उसके परिणामस्वरूप उत्पाद में लाभप्रदता और इसकी बिक्री मात्रा तथा बाजार हिस्से और उत्पादन, क्षमता का उपयोग, मालसूची, निर्यात पर उसके परिणामी प्रभाव में देखा जाता है।
- द. कद्दे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के संबंध में, वह वैश्विक कारक है और ऐसा केवल भारतीय बाजार में नहीं हुआ है। स्वतंत्र बाजार के रूप में, घरेलू उद्योग ऐसे कारकों के अनुरूप अपने उत्पाद की विधिवत् रूप से कीमत निर्धारण की हुई होती।
- ध. क्षमता के विस्तार के कारण लाभ पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग का लाभ और निवेश पर लाभ के संबंध में कार्य-निष्पादन में वर्तमान अवधि में तेजी से गिरावट आई जब क्षमता में कोई वृद्धि नहीं की गई थी।
- न. निर्णायक समीक्षा के अंतिम जांच परिणामों का संदर्भ लेने के बारे में यह नोट किया जाता है कि निर्णायक समीक्षा जांच परिणाम अप्रैल, 2016 से सितंबर, 2017 पर जांच की अवधि के रूप में आधारित है जबकि वर्तमान मामले में क्षति सबसे हाल की अवधि में और निर्णायक समीक्षा में जांच की गई पीओआई के बहुत बाद की अवधि में ज्यादा हुई है। इन दो अवधियों के बीच लागतों और कीमतों की तुलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि घरेलू उद्योग लागत में परिवर्तनों के अनुरूप अपनी कीमतों को निर्धारित करने में सक्षम नहीं था और इसके परिणाम के तौर पर लाभ में बहुत अधिक गिरावट का इसे सामना करना पड़ा।
- प. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिस उपाय की सिफारिश की गई है वह केवल कोरिया से आयातों तक सीमित रहेगा। अन्य सभी देशों से आयात बिना किसी रक्षोपाय उपाय के किया जाना जारी रहेगा। इसके अलावा, वर्तमान उपाय के फलस्वरूप कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा। वर्तमान जांच का उद्देश्य इस तथ्य की जांच करना था कि क्या पूर्व में दी गई शुल्क रियायत को वापस लिए जाने की आवश्यकता है। आपूर्ति के स्रोत को इन उपायों के परिणाम के तौर पर कटौती नहीं की जाएगी।
- फ. अनंतिम उपायों को लागू किए जाने के लिए औचित्य के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्रारंभिक जांच-परिणाम में कारण दिए गए हैं।
- प्राधिकारी ने क्षति के विश्लेषण के लिए 2019-20 की दूसरी तिमाही पर विचार करने हेतु प्रारंभिक जांच परिणाम में पर्याप्त औचित्य दिए थे। रक्षोपाय जांच में अगली तिमाही के आंकड़ों को जोड़ने की प्रथा रही है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों को 2019-20 की दूसरी तिमाही के लिए आंकड़ों के संबंध में अनुरोध करने हेतु दिए गए अपर्याप्त समय के बारे में, यह देखा गया है कि आवेदकों द्वारा 15 जनवरी को ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे और इस कारण से, अन्य हितबद्ध पक्षकारों के पास अपने अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय था। किसी भी मामले में, हितबद्ध पक्षकारों को प्रारंभिक जांच परिणाम और उसके बाद मौखिक सुनवाई के समय अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय मिला था, उनके पास मौखिक अनुरोध और उसके बाद लिखित अनुरोध तथा प्रति-उत्तर देने के लिए समुचित अवसर मिला

- था। इस प्रकार से हितबद्ध पक्षकारों के पास अपने विचारों को व्यक्त करने तथा अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए अनेक अवसर थे।
- ब. मांग और आपूर्ति में अंतर तथा पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त किए जाने के कारण कोरिया से आयातों की आवश्यकता के संबंध में यह देखा गया है कि उसी मात्रा में सभी स्रोतों से आयातों में वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि ये कोरिया से हुए हैं। सभी स्रोतों से आपूर्तिकर्त्ताओं को भारतीय बाजार में समान अधिकार मिलता है। इसके अलावा, मांग-आपूर्ति में अंतर अपने आप आयातों को न्यायोचित नहीं ठहराता है। हालांकि, इस जांच ने यह दर्शाया है कि घरेलू उद्योग कच्चे माल की कीमतों में परिवर्तनों के अनुरूप अपनी कीमतें निर्धारित करने में सक्षम नहीं था जिसके फलस्वरूप लाभप्रदता में बहुत अधिक गिरावट हुई है। इसके अलावा, मात्रा संबंधी अन्य मानदंडों में प्रवृत्तियां भी यह दर्शाती हैं कि घरेलू उद्योग को उस सीमा तक जिस सीमा तक यह बिक्री कर सकता था, बढ़े हुए कोरिया से आयातों के अभाव में रोका गया है। कोरिया से आयातों का हिस्सा कोरिया से आयातों के द्वारा प्राप्त प्रमुख स्थिति को दर्शाता है जिसे इस जांच परिणाम में संगत स्थानों पर जांच की गई अपेक्षाकृत अधिक लंबी अवधि के आयातों की प्रवृत्ति से स्पष्ट है।
- भ. निर्णायक समीक्षा जांच में यह भी देखा गया था कि कोरिया से अधिकांश निर्यात उस उत्पादक द्वारा किया जा रहा था जिस पर पाटनरोधी शुल्क की शून्य दर लग रही थी।
- म. इस अनुरोध के संबंध में कि प्रारंभिक जांच परिणामों की सिफारिश बहुत अधिक समय बीत जाने के बाद की गई थी, यह देखा गया है कि अंतरिम उपाय लागू करने के लिए सीईपीए के अंतर्गत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है और न ही अनंतिम उपायों को लागू करने में विलंब के कारण कोरिया के आपूर्तिकर्त्ताओं के हितों के साथ पक्षपात होता है। इसके अलावा, प्रारंभिक जांच-परिणाम को प्रकाशित किए जाने के पूर्व मौखिक सुनवाई के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अवसर उपलब्ध कराने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। मौखिक सुनवाई पर विचार अंतिम जांच परिणामों के प्रकाशन के पूर्व प्रक्रिया के एक भाग के रूप में किया जाता है। हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई किए जाने का एक अवसर दिया गया है। इन पक्षकारों ने लिखित रूप में अपने अनुरोध प्रस्तुत किए हैं और उसका निराकरण समुचित रूप से वर्तमान जांच परिणाम में किया गया है।
- य. गैर-संबद्ध देशों से आयात कीमत के संबंध में, सीआईएफ आधार पर कीमतों की तुलना करना उपयुक्त नहीं है। बाजार में कीमतों को भारत में उनकी पहुंच कीमत के आधार पर तुलना की जानी अपेक्षित है। यह तथ्य कि अन्य देशों से कीमतें उसी रेंज में रही हैं, केवल यह दर्शाता है कि कोरिया से आयातों की मात्रा पर विचार करते हुए तथा कोरिया से आयातों ने अन्य देशों और आपूर्तिकर्त्ताओं की कीमतों के लिए बेंच मार्क के रूप में काम किया है। इस कारण से यदि कुछ देशों से आयात की कीमतें कभी कभी किसी विशेष अवधि में कम भी हो गई थी तब उसका यह आशय नहीं है कि ये कीमतें बाजार में कीमतों की बेंच मार्किंग कर रही थी। समग्र रूप में तथ्यों न कि केवल अलग-अलग तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाने की आवश्यकता है। समग्र अवधि के लिए विशेषण यह दर्शाता है कि गैर-संबद्ध आयातों की कीमतें आमतौर पर कोरिया की कीमतों से अधिक हैं।
- कक. प्रारंभिक जांच परिणाम में जैसा कि नोट किया गया था, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव एक वैश्विक कारक है और यह केवल भारतीय बाजार के लिए विशिष्ट नहीं है। कीमतों में उतार-चढ़ाव से कोरिया के उत्पादक भी प्रभावित हुए होते। कोरिया की निम्न कीमतों की प्रतिस्पर्धा से मुक्त बाजार में, यदि कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव हुआ होता तब घरेलू उद्योग उसके अनुसार अपनी कीमतों का समायोजन किए होते। लेकिन घरेलू उद्योग को कोरिया से कम कीमत पर हुए आयातों के द्वारा अपनी कीमतों को समायोजित करने से रोका गया था। कीमत में बहुत अधिक सकारात्मक कटौती हुई है जो यह दर्शाता है कि यदि घरेलू उद्योग कच्चे माल में परिवर्तनों के अनुरूप अपनी कीमतें निर्धारण किए होते तब इन्हें और अधिक बिक्री का नुकसान हुआ होता।
- खख. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि वार्षिकीकृत आंकड़ों की तुलना समुचित नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन्होंने वास्तविक आधार पर आंकड़ों की तुलना की है। हालांकि जहां कहीं

भी अवधि की लम्बाई अलग-अलग है, उसे अन्य अवधि के लिए आंकड़ों से तुलना करते हुए वार्षिकीकृत किया गया है।

- गग. जहां तक जनहित के विरुद्ध शुल्कों के बारे में अनुरोध का प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि ये अनुरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकारों ने इस तथ्य को दर्शाते हुए कोई सत्यापन योग्य सूचना/साक्ष्य नहीं दिए हैं कि किस प्रकार से शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध होगा। सरकार ने पूर्व में जनहित में होते हुए रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने का निष्कर्ष निकालने के बाद इस उत्पाद पर वैश्विक रक्षोपाय शुल्क दो बार लगाया था। वर्तमान सिफारिश अतिरिक्त शुल्क लगाने के लिए नहीं है। यह पूर्व में दिए गए रियायत को वापस लेने के लिए है। अन्य प्रकार से भी, जनहित का क्षेत्र बहुत बड़ा है और यह केवल संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं के हितों तक सीमित नहीं है। यह शुल्क कोरिया से हो रहे आयातों के विरुद्ध ही है। ये आयात जारी भी रहेंगे यद्यपि सीमा शुल्क की एमएफएन दर पर जारी रहेगी तब आयात के सभी अन्य स्रोत खुले हुए हैं। यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है और घरेलू बाजार में अतिरिक्त आमदानी उपलब्ध रहेगी।
- घघ. पाटनरोधी शुल्क सहित उपाय तथा बीआईएस उपाय शुल्क उद्योग को संरक्षण नहीं देता है। बीआईएस को अलग-अलग उद्देश्यों के लिए कार्यान्वित किया गया है और वह बिना किसी भेदभाव के आधार पर लागू होता है। पाटनरोधी शुल्क पाटन की मार्जिन की सीमा तक ही लगाया जा सकता है और इसका उद्देश्य अनुचित व्यापार कार्य-पद्धति को रोकना है। इन उपायों का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना नहीं है बल्कि बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है।
- डड. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति रहित कीमत की गणना पाटनरोधी तंत्र के अंतर्गत भारत द्वारा अपनाई जा रही कमतर शुल्क नियम के अनुसरण में पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। हालांकि, वर्तमान जांच एक द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच है और ऐसी जांच में क्षति रहित कीमत अथवा क्षति मार्जिन की गणना करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- चच. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की कैपिटल खपत बहुत कम है और वह घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकता था।
- छछ. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने वर्तमान निर्धारण के लिए वास्तविक आंकड़ों पर विचार किया है। हालांकि, जहां कहीं भी अवधि की लंबाई 12 महीने नहीं है, वहां उसे यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि इस तुलना में अवधियों की विभिन्न लंबाईयों के कारण कोई हानि नहीं है, स्थापित कार्य-पद्धति के अनुसार 12 महीने की अन्य अवधियों से तुलना का प्रश्न है, तुलना करते समय वार्षिकीकृत किया जाता है।
- जज. इस अनुरोध के संबंध में कि आयातों में सीमा शुल्क में परिवर्तन के साथ वृद्धि नहीं हुई, प्राधिकारी यह मानते हैं कि अवधि की समग्रता पर विचार करने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचा जाना अपेक्षित है। उस समय अन्य कारक भी हो सकते हैं (उदाहरण के लिए, कुछ अवधियों में मौजूदा रक्षोपाय शुल्क अथवा पाटनरोधी शुल्क)। रियायत के पूर्व, रियायत और रियायत के पश्चात के चरण की अवधि सहित अपेक्षाकृत अधिक अवधि के दौरान आंकड़ों पर विचार करते हुए यह देखा जाता है कि इस उत्पाद के कोरिया से हुए आयातों में स्वतंत्र और सापेक्ष रूप में वृद्धि हुई है।
- झझ. घरेलू उद्योग को अन्य कारकों के कारण हुई क्षति के संबंध में यह देखा जाता है कि कोई प्रमाणिक सूचना अथवा साक्ष्य यह दर्शाने के लिए रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है कि क्षति का प्राथमिक कारण इस प्रकार का अन्य कारक है।
- जज. इस अनुरोध के संबंध में कि कीमतों में मार्च, 2020 के अंत में वैश्विक रूप से गिरावट आई है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के आयातों और आर्थिक मानदंडों की प्रवृत्तियों की लंबी अवधि में जांच की गई है। कीमतों में गिरावट यदि कोई वैश्विक घटना हुई हो तब उसका समाधान विशेष रूप से तब कोरिया से आयातों की पहुंच कीमत अन्य देशों से आयातों की पहुंच कीमत से कम था, निवारण किए जाने की आवश्यकता है। घरेलू बाजार में कीमतें आयात की कीमतों और कच्चे माल की लागत का एक

कारक है। इस कारण से वैश्विक बाजार में कीमतों में गिरावट घरेलू कीमतों को उतना प्रभावित नहीं किया होता यदि आयात रियायती शुल्क पर हुआ होता।

- टट. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग पिछले दशक के दौरान व्यापार उपचार जांच से संरक्षित रहा है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संरक्षण के रूप में व्यापार उपचार कार्यवाहियों को मानना उपयुक्त नहीं है और न ही इन कार्यवाहियों को केवल इस कारण से लागू किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने इसके लिए अनुरोध किया है। इन उपायों को सभी हितबद्ध पक्षकारों की भागीदारी से और गुणावगुण की पिछली जांच के बाद और कानून का विधिवत् पालन करते हुए एक अर्थ न्यायिक जांच करने के बाद लागू किया जाता है।
- ठठ. यह उल्लेख किया गया है कि अन्य देशों को निर्यातों में कमी का भारत में किए गए निर्यातों में कोई महत्व नहीं है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि जबकि भारत में आयातों में वृद्धि हुई है, अन्य देशों को आयातों में गिरावट आई है।
- डड. इस दावे के संबंध में कि लाभ में मामूली गिरावट आई है, यह नोट किया जाता है कि लाभ में गिरावट बहुत अधिक है। वास्तव में घरेलू उद्योग को 2019-20 की दूसरी तिमाही में हानि उठानी पड़ी।

घ.1 विचाराधीन उत्पाद

21. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद प्रशुल्क शीर्ष 29173500 के तहत आने वाला "फ्यैलिक एनहाइड्राइड" (जिसे पीएएन भी कहा जाता है) एक फ्यैलिक एसिड का एनहाइड्राइड है और ऑर्थोक्सिलीन अथवा नैफ्थालीन के उत्प्रेरक ऑक्सीकरण द्वारा वाणिज्यिक रूप से उत्पादित किया जाता है।
22. पीएएन एक रंगहीन ठोस है, जिसे फ्यैलिक एनहाइड्राइड फ्लैक्स, फ्यैलिक एनहाइड्राइड (98 प्रतिशत मिन.), फ्यैलिक एसिड एनहाइड्रस, फ्यैलिक एनहाइड्राइड (99.8 प्रतिशत मिन.), आदि कहा जाता है।
23. फ्यैलिक एनहाइड्राइड का उपयोग फ्यैलिक ईस्टर का उत्पादन करने के लिए किया जाता है जो प्लास्टिसाइजर के रूप में कार्य करता है। यह प्लास्टिक उद्योग में एक महत्वपूर्ण रासायनिक मध्यवर्ती है।

घ.2 घरेलू उद्योग

24. नियम 2(घ) द्विपक्षीय रक्षोपाय नियमावली, 2007 में निम्नलिखित उल्लेख है:

"घरेलू उद्योग" का अभिप्राय-

- (i) भारत के सीमा क्षेत्र में प्रचालित होने वाले समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्द्धी सामानों के समग्र रूप से उत्पादक; अथवा
- (ii) वे उत्पादक जिनका समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्द्धी सामानों के सामूहिक उत्पादन में उन सामानों के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख अनुपात हो;

25. वर्तमान आवेदन पत्र मैसर्स आईजी पैट्रोकेमिकल्स लि. और मैसर्स थिरुमलाई केमिकल्स लि. द्वारा दायर किया गया है। एसआई ग्रुप प्रा. लि. इस समय भारत में इस उत्पाद का एकमात्र अन्य ज्ञात उत्पादक है। एसआई ग्रुप प्रा. लि. ने जांच की शुरूआत के बाद निर्धारित प्रपत्र में सूचना दायर की, परंतु समय सीमा की समाप्ति के बाद दायर की। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की क्षति के संबंध में आवेदकों अथवा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं। आवेदकों का उत्पादन में कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा है। अतः नियमावली के अनुसार आवेदन पत्र आधार की अपेक्षा को पूरा करता है। इस प्रकार, आईजी पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और मैसर्स थिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग हैं।

घ.3 जांच की अवधि

26. जांच की शुरूआत के चरण में विचार की गई अवधि अप्रैल, 2015 से जून, 2019 थी। इसके अतिरिक्त, चूंकि यह एक रक्षोपाय जांच है, अतः विगत परिपाटी को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम के लिए सितंबर, 2019 तक की अवधि के आंकड़ों पर विचार किया है। घरेलू उद्योग ने मार्च, 2020 तक की अवधि के आंकड़े दिए हैं। हालांकि प्राधिकारी ने पहले ही सितंबर, 2019 तक की अवधि के लिए आंकड़ों को जोड़ दिया है,

फिर भी वह घरेलू उद्योग द्वारा तथा प्रारंभिक जांच परिणाम के माध्यम से हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया था, यह जांच अक्टूबर, 2019 में शुरू की गई थी और इस कारण से जांच की शुरुआत के बाद की अवधि के आंकड़ों पर विचार करना उपयुक्त नहीं है। इस कारण से, सितंबर, 2019 के बाद की अवधि के लिए आंकड़ों पर विचार प्रारंभिक जांच-परिणामों में नहीं किया गया है। इसके अलावा चूंकि हितबद्ध पक्षकारों ने चिताएं व्यक्त की हैं कि क्या इन रियायतों के परिणामस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में शुल्क रियायतों के कारण गिरावट आई है, प्राधिकारी ने 2007-08 की अवधि के लिए आंकड़ों पर भी विचार किया है जो आवेदन का हिस्सा था।

घ.4 गोपनीयता

27. नियमावली का नियम 6 सूचना की गोपनीयता से संबंधित है। गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।

घ.5 व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार के तहत सीमा शुल्क

28. भारतीय जनतांत्रिक सरकार और कोरिया की सरकार के बीच व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार के तहत रियायतों को ध्यान में रखते हुए फैलिक एनहाइड्राइड के आयातों पर सीमा शुल्क की दर निम्नलिखित थी:

लागू कर्तम छ्यूटी दर			
31 दिसंबर, 2009	10.94%	2010-11	10.55%
31 दिसंबर, 2010	9.38%	2011-12	8.99%
31 दिसंबर, 2011	7.81%	2012-13	7.42%
31 दिसंबर, 2012	6.25%	2013-14	5.86%
31 दिसंबर, 2013	4.69%	2014-15	4.30%
31 दिसंबर, 2014	3.13%	2015-16	2.74%
31 दिसंबर, 2015	1.56%	2016-17	1.17%
31 दिसंबर, 2016	0.00%	2017-18	0.00%
31 दिसंबर, 2017	0.00%	2018-19	0.00%
31 दिसंबर, 2018	0.00%	2019-20	0.00%

घ.6 सूचना का स्रोत

29. प्राधिकारी ने मात्रा और आयातों के मूल्य की गणना के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) पर विचार किया है। क्षति संबंधी सूचना पर विचार घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए आवेदन से किया गया है। 2007-08 से सूचना पर विचार घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए आवेदन से किया गया है।

क. कोरिया से स्वतंत्र रूप में आयात

30. आयातों का संचलन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

क्रम सं.	वर्ष	आयात मात्रा	प्रवृत्ति	सीमा शुल्क
		मी. टन	सूचकांक	
1	2015-16	25,252	100	2.74%
2	2016-17	33,766	134	1.17%
3	2017-18	41,664	165	0.00%
4	2018-19	49,081	194	0.00%
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	22,819	361	0.00%
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	26,007	412	0.00%

31. यह देखा जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात इस अवधि में पूर्ण दृष्टि से काफी बढ़े हैं।

ख. भारत में सकल आयातों के संबंध में आयात

32. कोरिया गणराज्य और अन्य देशों से संबद्ध सामानों के आयातों का हिस्सा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

क्रम सं.	वर्ष	आयात मी. टन में			आयातों में हिस्सा	
		कोरिया गणराज्य	अन्य देश	कुल आयात	कोरिया गणराज्य	अन्य देश
1	2015-16	25,252	53,866	79,118	32%	68%
2	2016-17	33,766	58,285	92,051	37%	63%
3	2017-18	41,664	88,775	1,30,439	32%	68%
4	2018-19	49,081	95,579	1,44,660	34%	66%
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	22,819	23,384	46,204	49%	51%
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	26,007	23,830	49,837	52%	48%

33. यह देखा जाता है कि कोरिया से विचाराधीन उत्पाद के आयातों का हिस्सा बढ़ती हुई प्रशुल्क रियायत से इस अवधि में बढ़ा जबकि अन्य देशों के हिस्से में गिरावट आई। कोरियाई आयातों का अब शुल्क रियायत पूर्ण मात्रा तक बढ़ने से भारी हिस्सा है। यहां तक कि जब कई अन्य देशों से आयात सूचित किए जा रहे हैं तो सामूहिक रूप से उनका हिस्सा अकेले कोरिया के हिस्से से कम है।

ग. भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों में बुद्धि

34. भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध सामानों के आयातों का संचलन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

	वर्ष	कोरिया आयात	भारतीय उत्पादन	मांग	निम्नलिखित की तुलना में आयात	
					उत्पादन	खपत
		मी. टन	मी. टन	मी. टन	%	%
1	2015-16	25,252	3,07,008	3,32,413	8%	8%
2	2016-17	33,766	2,96,561	3,39,251	11%	11%
3	2017-18	41,664	2,89,491	3,72,030	14%	11%
4	2018-19	49,081	2,75,492	3,82,583	18%	13%
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	22,819	65,086	97,163	35%	23%
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	26,007	62,061	1,05,209	42%	25%

35. यह देखा जाता है कि शुल्क विभागों में वृद्धि के साथ उत्पादन और खपत की तुलना में आयातों में काफी हद तक वृद्धि हुई है।

उ.7 क्षति

36. गंभीर क्षति नियमावली के तहत निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

(च) गंभीर क्षति का अर्थ किसी घरेलू उद्योग की स्थिति में काफी समग्र हानि है; और

(छ) "गंभीर क्षति के खतरे" का अर्थ है कि वह गंभीर क्षति जो तथ्यों के आधार पर न कि केवल आरोप, अनुमान अथवा सुदूर संभावना पर स्पष्ट रूप से आसन हो; और

37. इस प्रकार, आयातों में वृद्धि वह होनी चाहिए जो घरेलू उद्योग की स्थिति में काफी समग्र हानि करें।

38. नियमावली के नियम 7 में भी निम्नलिखित प्रावधान है:

प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति का खतरा निर्धारित करेंगे, यथा:-

(क) प्राधिकारी पूर्ण दृष्टि से और सापेक्ष दृष्टि से मूल देश के सामान के आयातों में वृद्धि की दर तथा मात्रा, मूल के सामान के बढ़े हुए आयातों द्वारा लिए गए घरेलू बाजार के हिस्से, बिक्री, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग, लाभ और हानि तथा रोजगार के स्तर में परिवर्तन को विशेष रूप से उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले वस्तुपरक एवं मात्रात्मक सभी संगत कारकों का मूल्यांकन करेंगे; और

(ख) इस नियम के तहत निर्धारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक जांच वस्तुपरक साक्ष्य के आधार पर मूल देश के सामान के बढ़े हुए आयातों तथा उसकी गंभीर क्षति अथवा खतरे के बीच कारणात्मक संपर्क की मौजूदगी न दर्शाए और जब मूल देश के सामान के बढ़े हुए आयातों को छोड़कर कोई अन्य कारक साथ ही घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हों तो वह क्षति मूल देश के सामानों के बढ़े हुए आयातों के कारण नहीं होगी।

39. यह नोट किया जाता है कि सूचीबद्ध मानदंडों का मूल्यांकन विभिन्न उद्योगों और स्थितियों की विशेषताओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अतः प्राधिकारी ने वर्तमान मामले के तथ्यों और उद्योग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की जांच की है। इस प्रकार, सभी सूचीबद्ध कारकों और किन्हीं अन्य संगत कारकों की तकनीकी जांच के अलावा, यह अनिवार्य है कि उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी

संगत कारकों के आलोक में उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन किया जाए। तदनुसार, गंभीर क्षति का विश्लेषण करने में सभी कारकों, जो नियमों में उल्लिखित हैं तथा अन्य कारकों जो गंभीर क्षति के निर्धारण के लिए संगत हैं, पर विचार किया गया है। गंभीर क्षति का निर्धारण उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत कारकों के आलोक में घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति के मूल्यांकन पर आधारित है।

क. पूर्ण एवं सापेक्ष दृष्टि से आयातों में वृद्धि

40. यह देखा जाता है कि संबद्ध सामानों के आयातों में पूर्ण दृष्टि से तथा भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में काफी वृद्धि हुई है। यह भी देखा जाता है कि आयात कोरियाई आयातों को दी गई पूर्ण रियायतों से काफी बढ़े।

ख. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

41. क्षमता, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	वर्ष	क्षमता	उत्पादन	क्षमता उपयोग	घरेलू बिक्री	निर्यात बिक्री	कोरिया से आयात
		मी. टन ट्रैंड	मी. टन ट्रैंड	% ट्रैंड	मी. टन ट्रैंड	मी. टन ट्रैंड	मी. टन
1	2015-16	100	100	100	100	100	25,252
2	2016-17	100	97	97	98	103	33,766
3	2017-18	100	100	100	102	98	41,664
4	2018-19	100	97	98	104	63	49,081
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	100	91	92	89	70	22,819
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	100	87	88	96	92	26,007

42. यह देखा जाता है कि:-

- क. घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में इस अवधि में गिरावट आई है।
- ख. जबकि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री 2018-19 तक बढ़ रही थी तो उसमें काफी गिरावट आई है।
- ग. निर्यात बिक्री में 2018-19 में गिरावट आई है और उसके बाद वृद्धि हुई। आवेदक ने यह दावा किया है कि यह संबद्ध देश से आयातों के कारण निर्यात करने के लिए मजबूर था। यह देखा जाता है कि निर्यातों की लाभप्रदता घरेलू बिक्री की तुलना में बहुत प्रतिकूल है।

ग. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्ता

43. बाजार हिस्से का चलन निम्नलिखित था:

क्रम सं.	वर्ष	घरेलू उद्योग रेज	कोरियाई आयात	अन्य उत्पादक रेज	अन्य देश	कुल
1	2015-16	60-70%	8%	5-15%	16%	100%
2	2016-17	60-70%	10%	5-15%	17%	100%
3	2017-18	55-65%	11%	0-10%	24%	100%
4	2018-19	55-65%	13%	0-10%	25%	100%
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	45-55%	23%	0-10%	24%	100%
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	45-55%	25%	0-10%	23%	100%

44. यह देखा जाता है कि जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई, तो कोरियाई आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई। समग्र आधार पर, जबकि घरेलू उद्योग ने इस अवधि में 16 प्रतिशत बाजार हिस्सा खोया तो कोरियाई आयातों में लगभग उसी स्तर तक बाजार हिस्सा प्राप्त किया।

घ. रोजगार एवं उत्पादकता

45. रोजगार एवं उत्पादकता संबंधी आंकड़े निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	वर्ष	कर्मचारियों की संख्या	प्रति दिन उत्पादकता	प्रति कर्मचारी उत्पादकता
		सं.	मी. टन/दिन	मी. टन/सं.
1	2015-16	100	100	100
2	2016-17	100	97	97
3	2017-18	101	100	99
4	2018-19	103	97	95
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	103	92	89
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	103	87	85
7	अप्रैल से सितंबर, 19	103	89	87

46. प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में हाल के वर्षों में गिरावट देखी गई। तथापि, आवेदकों ने अनुरोध किया कि इन कारणों के निष्पादन कई अन्य मानदंडों पर निर्भर हैं और आयातों से सीधे ही जुड़े हुए नहीं हैं।

इ. मालसूची

47. मालसूची संबंधी आंकड़े निम्नलिखित दर्शाते हैं:

क्रम सं.	विवरण	औसत स्टॉक (मी. टन)
1	2015-16	100
2	2016-17	121
3	2017-18	72
4	2018-19	71
5	अप्रैल, 19-जून 19	140
6	जुलाई, 19-सितं. 19	132

48. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग में मालसूची का स्तर इस अवधि में बढ़ा।

च. लाभ/हानि

49. लाभ तथा नियोजित पूँजी पर आय संबंधी आंकड़े निम्नलिखित दर्शाते हैं:

क्र.सं.	वर्ष	लाभ/(हानि)		आरओआई
		लाख रु.	रु./मी. टन-प्रवृत्ति	
1	2015-16	100	100	100
2	2016-17	285	291	205
3	2017-18	584	570	295
4	2018-19	407	392	216
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	104	467	53
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	-13	-54	5

50. यह देखा जाता है कि लाभ तथा नियोजित पूँजी पर आय में 2017-18 के बाद तेजी से ह्रास हुआ है। घरेलू उद्योग को जुलाई से सितंबर, 2019 की सबसे हाल की अवधि में वित्तीय हानियां हुई हैं।

छ. कीमत कटौती

51. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की कि क्या कोरिया से आयात बाजार में उत्पाद की कीमतें निर्धारित कर रहे थे। इस प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने कोरिया से आयातों की पहुँच कीमत तथा घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से विभिन्न देशों से आयातों की पहुँच कीमत की तुलना की।

क्रम सं.	वर्ष	एनएसआर	पहुँच कीमत	कीमत कटौती	कीमत कटौती
		रु./मी. टन-प्रवृत्ति	रु./मी. टन	रु./मी. टन	% रेज
1	2015-16	100	56,387	*****	0-10%
2	2016-17	113	61,185	*****	5-15%
3	2017-18	119	66,989	*****	0-10%
4	2018-19	135	74,225	*****	0-10%
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	126	68,900	*****	5-15%
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	112	63,618	*****	0-10%
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	112	63,618	*****	0-10%
7	अप्रैल से सितंबर, 19	119	66,086	*****	0-10%

52. यह देखा जाता है कि आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रही है। इस प्रकार, आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रही थी।
53. प्राधिकारी ने कोरिया से आयातों की पहुँच कीमत के साथ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, बिक्री कीमत में प्रवृत्तियों की जांच की। यह देखा जाता है कि क्योंकि आयातों की पहुँच कीमत पूर्व में बिक्री लागत से अधिक थी तो हाल की अवधि में आयातों की पहुँच कीमत बिक्री लागत से कम है। यदि घरेलू उद्योग ने इन आयात कीमतों पर बिक्री की होती तो वर्तमान अवधि में उसे हानियां हुई होतीं।

क्रम सं.	वर्ष	बिक्री की लागत	बिक्री कीमत	पहुँच कीमत
		रु./मी. टन-प्रवृत्ति	रु./मी. टन-प्रवृत्ति	रु./मी. टन
1	2015-16	100	100	56,387
2	2016-17	105	113	60,274
3	2017-18	99	119	66,989
4	2018-19	123	135	74,225
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	127	126	68,900
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	118	112	63,618
7	अप्रैल से सितंबर, 19	122	119	66,086

घ. निष्कर्ष

54. यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में पूर्ण दृष्टि से तथा भारत में सकल आयातों के संबंध में, भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में काफी वृद्धि हुई है। आयातों के कारण घरेलू कीमतों में कटौती हो रही थी। आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी। कोरिया से आयातों में अचानक बहुत अधिक वृद्धि के फलस्वरूप घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट आई है जिसे उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा, लाभ, निवेश पर आय में गिरावट तथा बढ़ते हुए कम लाभप्रद निर्यातों और बढ़ती हुई मालसूची के संदर्भ में गंभीर क्षति हुई है। विभिन्न मानदंडों के संबंध में, घरेलू उत्पादक के निष्पादन पर विचार करते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग को कोरियाई आयातों को दी गई शुल्क रियायतों के परिणामस्वरूप गंभीर क्षति हुई है जिससे कोरिया से कम कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद के आयात बढ़े।

च. गंभीर क्षति का खतरा

55. नियमावली में निम्नलिखित प्रावधान है:

"गंभीर क्षति का खतरा" का अर्थ है गंभीर क्षति जो स्पष्ट रूप से आसन्न हो और तथ्यों के आधार पर निर्धारित की जाएगी न कि केवल आरोप, अनुमान अथवा सुदूर संभावना पर;

56. यह नोट किया जाता है कि कोरिया से संबद्ध आयात पूर्ण दृष्टि से तथा भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में काफी बढ़ी हुई मात्राओं में भारतीय बाजार में आ रहे हैं। घरेलू उद्योग की क्षमता का उपयोग कम हुआ था और कोरिया से बढ़े हुए आयातों ने स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। संबद्ध सामानों के आयातों की पहुंच कीमत, कोरिया में उनकी निर्यातोन्मुखता के साथ भारी क्षमताओं के बीच अंतर को ध्यान में रखते हुए यह सिद्ध है कि कोरिया से संबद्ध सामान कीमत आकर्षक रहने की संभावना है जो घरेलू उद्योग को क्षति का न्यूनतम खतरा पैदा कर रहे हैं। गंभीर क्षति का खतरा निम्नलिखित कारकों से सिद्ध है:

- क. घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच कीमत अंतर से कोरिया से संबद्ध सामानों के आयातों में वृद्धि हुई है।
- ख. कोरिया के उत्पादकों के पास काफी अनुपर्युक्त क्षमताएँ हैं,
- ग. भारत को कोरिया से आयातों में वृद्धि हुई है और विश्व के शेष देशों को निर्यात में गिरावट आई है। भारत में कोरिया से निर्यातों में वृद्धि है और शेष विश्व को निर्यातों में गिरावट है।
- घ. उत्पाद की मांग बढ़ रही है और भारतीय बाजार व्यापक और कीमत संवेदी है।
- ङ. आयातों की मात्रा का अधिक होना जारी था और घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन हाल की अवधि में प्रतिकूल रहना जारी था।

उपर्युक्त के महेनजर, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कोरिया से संबद्ध सामानों के बढ़े हुए आयातों से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है।

छ. कारणात्मक संबंध

57. ऊपर दिए गए अनुसार घरेलू उद्योग के निष्पादन का व्यापक मूल्यांकन यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है और कोरिया से बढ़े हुए आयातों से और भी गंभीर क्षति का खतरा है। प्राधिकारी ने इस बात की जांच की कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति शुल्क रियायतों तथा परिणामस्वरूप कोरिया से आयातों में वृद्धि के कारण है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों के इन तर्कों के महेनजर कि प्राधिकारी को इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या दावा की गई क्षति शुल्क रियायतों के कारण है अथवा किन्हीं अन्य कारकों से है, प्राधिकारी ने उस अवधि सहित मंदी अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन पर भी विचार किया जब शुल्क रियायत नहीं थी। इस निमित्त संगत सूचना घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन पत्र में निहित है जिसे हितबद्ध पक्षकार आवेदन पत्र तथा अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर के माध्यम से देख सकते हैं।
- क. प्राधिकारी ने यह जांच कि क्या किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो सकती थी। प्राधिकारी ने विभिन्न जांच मानदंडों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए मानदंडों पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि घरेलू उद्योग को सूचित क्षति इस समय प्रचालित हो रहे अन्य कारकों की संभावित मौजूदगी के कारण नहीं है।
 - ख. कोरिया से उत्पाद के आयातों में कोरियाई आयातों को प्रशुल्क रियायतों में वृद्धि तथा उसके सीमा शुल्क की समाप्ति से काफी वृद्धि हुई है।

- ग. पूरी शुल्क रियायतों से कोरियाई आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। कोरियाई कीमतें ही बाजार में उत्पाद की कीमतों का निर्धारण कर रही थीं।
- घ. कोरिया से आयातों की पहुँच कीमत अब घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम है।
- ड. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग इष्टतम स्तर से कम है और परिणामस्वरूप उत्पादन में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्री में शुल्क रियायतों के परिणामस्वरूप बढ़ते हुए आयातों से गिरावट आई है। घरेलू बिक्री में गिरावट और बढ़ती हुई मालसूची भारत में आयातों में वृद्धि का परिणाम है।
58. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को क्षति बढ़े हुए आयातों के कारण हुई है और कोरिया से संबद्ध सामानों के बढ़े हुए आयातों और कोरियाई आयातों को दी गई शुल्क रियायतों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति तथा गंभीर क्षति के खतरे के बीच कारणात्मक संबंध है।

ज्ञ. समायोजन योजना

59. आवेदकों ने जांच प्रक्रिया के दौरान समायोजन योजनाओं के ब्यौरे दिए हैं। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि समायोजन योजना में यथा-उल्लिखित घटती हुई लागतों के प्रति निर्देशित उपाय वह कर रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा दी गई समायोजन योजना के संबंध में प्राधिकारी नीचे दिए गए अनुसार नोट करते हैं।
- क. आईजी पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने समायोजन योजना तैयार की है जिसमें मौजूदा उत्प्रेरक को बदलकर कच्ची सामग्री लागत में कमी करने संबंधी कार्रवाई योजना, वसूलियों में सुधार, विद्युत एवं ईंधन लागत में कमी, क्षमता अभिवृद्धि तथा मौजूदा संयंत्रों की यूटिलिटियों को एकीकृत करने, प्रशासनिक खर्चों, कार्मिक लागत और वित्तीय लागत के निमित्त लागतों को कम करने के प्रयास शामिल हैं। यह देखा जाता है कि कंपनी ने *** करोड़ रु. की पूँजीगत व्यय से 53,000 मी.टन तक क्षमता में विस्तार करने की योजना बनाई है। इसके फलस्वरूप कंपनी के लिए लागत में बहुत अधिक कटौती हुई है।
- घ. थिरूमलाई केमिकल्स ने एक समायोजन योजना तैयार की है जिसमें उच्चतम क्षमता तथा दक्षता के लिए उपस्करों का उन्नयन कर लागत में कमी, उत्पादन में सुधार, ऊर्जा लागतों में कमी, तेल खपत में कमी, वेतन एवं मजदूरियों, भंडार तथा अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों, मरम्मत एवं रख-रखाव तथा प्रशासनिक ऊर्परी खर्चों में कमी शामिल है। कंपनी ने यह सूचित किया है कि उसने 1,20,000 मी.टन तक क्षमता का विस्तार करने की योजना बनाई है। कंपनी ने *** करोड़ रु. के पूँजीगत व्यय के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। इसके फलस्वरूप कंपनी की लागत में बहुत अधिक कटौती हुई है।
60. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदकों ने कोरिया से आयातों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनने के लिए समायोजन योजना तैयार की है।

ज्ञ. जनहित

61. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि रक्षोपाय शुल्क लगाने से जनहित को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचेगा क्योंकि काफी संख्या में अंतिम प्रयोक्ता उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा। यह भी तर्क दिया गया है कि रक्षोपाय शुल्क लगाने से यह और महंगा हो जाएगा तथा यह उपभोक्ता के हित के विरुद्ध होगा। देश में मांग और आपूर्ति के अंतर के बारे में चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं।
62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मौजूदा उपाय कोई अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रति नहीं है बल्कि पूर्व में दी गई रियायत को वापस करने के प्रति है और वह भी केवल कोरिया से आयातों के मामले में। सभी अन्य स्रोतों से आयात प्रस्तावित उपायों से पूर्ण रूप से अप्रभावित हैं।
63. मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त घरेलू क्षमता की चिंताओं के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग कोरिया से हुए आयातों के न होने की स्थिति में घरेलू मांग की उच्चतर प्रतिशत को पूरा कर सकता था। किसी भी स्थिति में कोरिया से आयात प्रस्तावित उपाय को लागू किए जाने के बाद भी सीमा शुल्क की एमएफएन दर पर उपलब्ध रहना जारी रहेगा। इसके अलावा, सभी अन्य स्रोतों से आयात भी सुगम्य रहेंगे। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है। विस्तार के पूरा हो जाने के बाद, इस उत्पाद के लिए भारतीय सकल क्षमता 4,04,744 मी.टन की मौजूदा मांग की तुलना में 4,84,000 मी.टन होगी। किसी भी स्थिति में आयात घरेलू क्षमताओं से मांग के अधिक होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को सभी स्रोतों से खुली है।

64. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य और सूचना उपलब्ध नहीं कराए हैं कि किस प्रकार से वर्तमान द्विपक्षीय उपायों को लागू करने के फलस्वरूप असहनीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हितबद्ध पक्षकारों ने केवल यह स्वीकार किया है कि यह उत्पाद एक मध्यवर्ती उत्पाद है और शुल्कों को लगाने का प्रयोक्ता उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इन पक्षकारों ने कोई संबंधित आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि वैश्विक रक्षोपाय उपाय जनहित पर उचित विचार करने के बाद इस उत्पाद पर पहले भी लगाया गया है।

अ. निष्कर्ष एवं सिफारिश

65. उपर्युक्त जांच के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि संबद्ध सामानों के बढ़े हुए आयातों से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है। द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय लगाए जाने के संबंध में भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय) की नियमावली, 2017 के नियम 10 में निम्नलिखित उल्लेख है:

(1) महानिदेशक जांच की शुरुआत की तिथि से 8 महीने के भीतर अथवा इस जांच की शुरुआत की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के भीतर जिसे केन्द्र सरकार अनुमति दे सकती है, इस तथ्य का निर्धारण करेंगे कि क्या-

(क) जांच के अधीन मूल वस्तु के बढ़े हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई अथवा होने का खतरा है। और

(ख) व्यापार करार के अंतर्गत सीमा शुल्क में कटौती अथवा उसकी समाप्ति के कारण मूल वस्तु के बढ़े हुए आयातों और गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे के बीच कारणात्मक संबंध है।

(2) महानिदेशक द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय के संबंध में अपनी सिफारिश भी देंगे जो गंभीर क्षति को रोकने अथा उसका उपचार करने तथा समायोजन को आसान बनाने के लिए पर्याप्त होगा।

(3) महानिदेशक द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय की अवधि के संबंध में अपनी सिफारिशें भी देंगे:

बशर्ते कि जहां सिफारिश की गई अवधि एक वर्ष से अधिक हो, महानिदेशक समायोजन को आसान बनाने के लिए पर्याप्त आवेदन की अवधि के दौरान नियमित अंतरालों पर द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय एक प्रगामी उदारीकरण की भी सिफारिश कर सकते हैं।

66. उपर्युक्त की जांच करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि:

क. कोरिया से उत्पाद के आयातों में वृद्धि हुई है और इस नियमावली तथा कोरिया-भारत सीईपीए के अभिप्राय से “बढ़ा हुआ आयात” है।

ख. बढ़े हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है और गंभीर क्षति होने का खतरा है।

ग. कोरिया-भारत सीईपीए के अंतर्गत सीमा शुल्क में कटौती अथवा उसकी समाप्ति के कारण मूल वस्तु के बढ़े हुए आयातों और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति तथा गंभीर क्षति के खतरे के बीच एक कारणात्मक संबंध है।

67. भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय) नियमावली, 2017 के संदर्भ में द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय सिफारिश करना उपर्युक्त माना जाता है। तदनुसार, प्राधिकारी कोरिया गणराज्य के मूल की संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर व्यापार करार के लागू होने की तिथि के ठीक पहले की तिथि को संबद्ध वस्तुओं पर सीमा शुल्क की लागू एमएफएन दर अथवा द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय के लागू होने की तिथि को संबद्ध वस्तुओं पर सीमा शुल्क की एमएफएन दर, इसमें जो भी कम हो, तक सीमा शुल्क की दर बढ़ाने की सिफारिश करते हैं। इस उपाय की सिफारिश केन्द्र सरकार द्वारा 6 जुलाई, 2020 की अधिसूचना सं. 29/2020-सीमा शुल्क के

माध्यम से अनंतिम शुल्क लगाए जाने की अधिसूचना के जारी होने की तिथि से नीचे दी गई तालिका के अनुसार दो वर्षों की अवधि के लिए की जाती है।

वर्ष	द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय
प्रथम वर्ष	100 प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क की दर को एमएफएन सीमा शुल्क की लागू दर के स्तर तक बढ़ाना
द्वितीय वर्ष	75 प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क की दर को एमएफएन सीमा शुल्क की लागू दर के स्तर तक बढ़ाना

68. उपर्युक्त के अध्यधीन, दिनांक 11 मई, 2020 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित प्रारंभिक जांच परिणाम की एतद्वारा पुष्टि की जाती है।

बी.बी.स्वैन, विशेष सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 28th September, 2020

Case No: SG-08/2019

Subject: Final Findings of Bilateral Safeguard Investigation concerning imports of "Phthalic Anhydride" into India from Korea under India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017

F. No. 22/8/2019-DGTR.—A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Having regard to the Article 2.22 of the Comprehensive Economic Cooperation Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Korea (CEPA) and India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 (hereinafter referred to as the "Rules" or "Bilateral Safeguard Rules") thereof, I G Petrochemicals Limited and Thirumalai Chemicals Limited (hereinafter referred to as the "Applicants") have filed an application before the Director General of Trade Remedies (herein after referred to as the "Authority" or "Director General") in accordance with CEPA and Bilateral Safeguard Rules for initiation of bilateral safeguard investigation concerning increased imports of Phthalic Anhydride (PAN) (hereinafter referred to as the "product under consideration" or "subject goods") from Korea (hereinafter referred to as "subject country").
2. The Authority on the basis of prima facie evidence submitted by the Applicants, issued notification number SG-08/2019 dated 1st October 2019, published in the Gazette of India, initiating the investigation in accordance with the Rules.
3. The request made by the domestic industry for imposition of provisional safeguard duty was examined and it was provisionally determined that critical circumstances existed which warranted imposition of provisional safeguard duty. Preliminary findings were issued vide Notification No. 22/8/2019- DGTR dated 11th May 2020, recommending imposition of provisional safeguard duty on the imports of subject goods originating in or exported from Korea. The Central Government vide Notification No. 29/2020-Customs dated 6th July 2020 imposed provisional safeguard measures by eliminating the concessions given under the CEPA and increased the rate of custom duty to 7.5% on imports of subject goods to originating in or exported from the Korea for a period of 200 days.

B. PROCEDURE

4. The procedure described below has been followed with regard to the investigation-
- a. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 1st October, 2019 to the Central Government in the Ministry of Commerce and Industry and other Ministries concerned, Government of Korea through the Embassy of Republic of Korea in India, the known producers and exporters in the subject country and known importers and other interested parties as mentioned in the application, in accordance with Rule 5(2) of the said Rules.
 - b. Copy of the non-confidential version of the application filed by the Applicants was made available to the Central Government in the Ministry of Commerce and Industry and other Ministries concerned, Government of Korea through the Embassy of Republic of Korea in India and the known producers and exporters in the subject country in accordance with Rule 5(3) of the Rules.
 - c. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating bilateral safeguard investigation to the following known producers/exporters in the subject country and provided them an opportunity to file response to questionnaire in the form and manner prescribed and make their views known in writing within thirty days in accordance with the Rules 5(4) of the Rules:
 - i. Aekyung Petrochemical Co. Ltd.
 - ii. LG Petrochemical, Yeochon
 - iii. Hanwha Chemical Corporation
 - iv. OCI Company Limited
 - d. In response to the questionnaire issued, all four producers/exporters filed exporter's questionnaire response.
 - e. The Authority sent Importer Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 5(5) of the Rules:
 - i. Cray Valley Resins India Limited
 - ii. Goodless Nerolac Paints Limited
 - iii. Gargi Industries Limited
 - iv. Hindustan Insecticides Limited
 - v. Kemrock Industries & Exports Limited.
 - vi. Shalimar Paints Limited,
 - vii. U.K. Paints India Private Limited.
 - f. In response, the following importers have filed questionnaire response:
 - i. Sandeep Organics Private Limited
 - ii. Unity Organics Private Limited
 - iii. Nishant Organics Private Limited
 - iv. Dhanlaxmi Pigments Private Limited
 - v. Kesar Petroproducts Limited
 - vi. Mazda Colours Limited
 - vii. Shiv Dyestuff Intermediate Industries
 - viii. A-One Phthalo Colours Private Limited
 - ix. A-One Chemicals Limited
 - x. Narayan Organics Private Limited
 - xi. Narayan Industries
 - xii. PCL Oil & Solvents Limited
 - xiii. KLJ Plasticizers Limited
 - xiv. Rachna Plasticizers
 - xv. Payal Polyplast Private Limited

- xvi. Asian Paints Limited
- xvii. Kansai Nerolac Paints Limited
- xviii. Shalimar Paints Limited
- xix. Berger Paints India Limited
- g. The Authority also sent questionnaire to the domestic industry. The domestic industry filed its questionnaire response.
- h. The following interested parties filed submissions responding to the initiation notification:
 - i. Chemexcil (Basic Chemicals, Cosmetics & Dyes Export Promotion Council)
 - ii. The Gujarat Dyestuff Manufacturers Association
 - iii. Korea Petrochemical Industry Association on behalf of Aekyung Petrochemical Co Ltd., Hanwha Chemical Corporation, OCI Company Ltd. & LG Chern Ltd.,
 - iv. Government of Korea
 - v. Indian Paint Association
 - vi. KLJ Plasticizers Ltd.,
 - vii. Payal Polyplast Pvt Ltd.,
 - viii. Rachna Plastics
 - ix. PCL Oil & Solvents Ltd.
- i. After the issuance of the preliminary findings, the Director General held an oral hearing on 11th August 2020 in terms of Rule 5(6) of the Rules, where opportunity was provided to all interested parties to present their views. Thereafter, the interested parties were given opportunity to present their views in writing and offer comments on views expressed by other interested parties. Copy of written submissions filed by interested parties post oral hearing were made available to other interested parties. Interested parties were also given an opportunity to file rejoinders, if any, to the written submissions of other interested parties.
- j. Post issuance of the preliminary finding, comments were filed by the following interested parties: -
 - i. Government of Korea (GOK)
 - ii. Indian Paint Association
 - iii. Korea Petrochemical Industry Association
 - iv. KLJ Plasticizers Limited,
 - v. Payal Polyplast Private Limited,
 - vi. Rachna Plastics
 - vii. PCL Oil & Solvents Limited.
- k. Written submissions and rejoinders post oral hearing were filed by the following interested parties: -
 - i. Domestic industry
 - ii. Government of Korea
 - iii. Indian Paint Association
 - iv. Korea Petrochemical Industry Association
 - v. The Gujarat Dyestuff Manufacturer's Association
 - vi. Indian Plasticizers Manufacturers Association (IPMA)
- l. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- m. The Government of Korea (GOK) availed the opportunity of consultations which were held on 15th September, 2020. Concerns raised by GOK have been examined and addressed. Further, concerns raised by GOK have been raised through written submissions earlier have also been duly considered and appropriately addressed in the present findings.

- n. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this final finding.

C. Submissions made by the Applicants and other interested parties

C.1. Product under consideration

5. The submissions made by the Applicants in respect of product under consideration are as follows:
 - a. The product under investigation is “Phthalic Anhydride”, falling under the HS code 29173500. Product under consideration is commonly used to produce Phthalate esters, which function as plasticizers.
 - b. The product being produced by the domestic industry is like article to imported product. The domestic product is comparable to the imported product.
6. No submission has been made by other interested parties in respect of product under consideration.

C.2. Domestic industry

7. The Applicant has contended that apart from them, there are two existing producers in India, namely SI Group Limited and Asian Paints. Asian Paints has permanently shut down its plant in July 2017.
8. No submissions have been made by other interested parties in respect of scope of the domestic industry.

C.2. Confidentiality

9. The submissions made by other interested parties in respect of confidentiality are as follows:
 - a. The Applicants have claimed excessive confidentiality in their Application as the data which was available in the final finding of the anti-dumping investigation has not been disclosed. Further, the requirements of the trade notice 10/2018 have not been complied with.
 - b. Adjustment plan is vague, excessively confidential. The applicants failed to provide summarized/ non-confidential version of the adjustment plan which has deprived the interested parties of an opportunity to present its views on the viability of the adjustment plan.
 - c. Domestic industry has claimed confidentiality about capacity expansion However, this was disclosed in the oral hearing. Therefore, the information cannot be claimed as confidential.

C.3. Miscellaneous Submissions

10. The submissions made by the applicants are as follows:
 - a. With regard to adjustment plans, the domestic industry has submitted that it is taking measures to reduce costs. IG Petrochemicals has given an adjustment plan which includes action on reduction in raw material cost by replacing existing catalyst, improvement in recoveries, reduction in power and fuel cost, capacity additions and integrating utilities of existing plants, efforts to reduce costs on account of administrative overheads, personnel cost and finance cost. Thirumalai Chemicals has given an adjustment plan which includes reduction in cost by upgrading equipment for higher capacity & efficiency, improvement in yield, reduction in energy costs, reduction in oil consumption, reduction in wages & salaries, stores & spares, repair & maintenance and administrative overheads.
 - b. Measures are necessary for a minimum period of 4 years in order to enable the domestic industry to successfully implement its adjustment plan.
 - c. Applicants are in the process of expanding their capacities for the product under consideration which are expected to reach 4,84,000 MT for which they have incurred significant amount. The capacity will then be more than the demand in India.
 - d. In past when protection was not provided for requested period, the domestic industry was not able to adjust itself.
 - e. Decisions of capacity expansions are not taken overnight but happen over a period. Decision to expand capacity were taken when the domestic industry was in profits.
 - f. Capacity expansion will ensure that the capacity in India will be more than the demand in the country.
 - g. The past anti-dumping duties were not protection to domestic industry but only to counter the effect of dumping by the foreign producers.
 - h. Applicants have requested only for suspension of concessions on imports from Korea to restore fair competition.
 - i. BIS standard will only provide better quality to the consumers.
 - j. The consumers have made baseless allegations about producers not responding to customer inquiries.

11. The submissions made by other interested parties are as follows:
- a. The application does not contain any evidence to satisfy the requirements of the Rules.
 - b. The present investigation should be terminated as the substantive requirements of a valid bilateral safeguard measure have not been satisfied as the standards required for a safeguard investigation are much higher.
 - c. The application is deficient as the data provided by the domestic industry does not correspond to the period identified in the initiation notification.
 - d. The Applicants have not brought forward sufficient evidence to prove the conditions for initiation of the bilateral safeguard investigation. The four conditions laid down in Article 2.22 are not satisfied.
 - e. Initiation of investigation is invalid and inconsistent under Rule 4(2)(b) of the Bilateral SG Rules which concerns obligation at the pre-initiation stage. The deficiency of not providing an adjustment plan at the time of the initiation of this investigation cannot be cured by subsequently providing an adjustment plan.
 - f. Domestic industry in the previous global safeguard investigation had submitted a similar adjustment plan which it did not implement. This was considered as a main reason for not extending the safeguard protection by DG Safeguards
 - g. View taken by the DG on adjustment plan is not as per the legal requirements of the bilateral safeguard measures.
 - h. Domestic industry's stance has changed regarding adjustment plan from application to questionnaire response and final adjustment plan which shows lack of planning to positively adjust to the competition from imports.
 - i. The initiation nowhere discloses whether domestic industry has submitted any adjustment plan to indicate how they will achieve increase in productivity, decrease in cost and above all reduction in their selling prices to meet international competition.
 - j. Present investigation should be terminated in view of initiation of parallel anti-dumping investigation against Korea and other countries as there cannot be a simultaneous imposition of bilateral safeguard duty along with anti-dumping duty for the same product with overlapping POI.
 - k. The provisional measures were recommended after a substantial passage of time as against the practice of recommending them within 1-3 months.
 - l. No opportunity for hearing was given to interested parties before provisional finding and every issue should be examined afresh
 - m. The capacity expansions proposed by the applicants are futuristic scenario which are never put into effect and do not scuttle submission that users were compelled to import because of demand-supply gap.
 - n. There exists significant demand-supply gap and therefore the product under consideration will be imported into India and the domestic industry has not expanded its capacity.
 - o. There have been two safeguard measures and anti-dumping measures in about 10 years, and the Applicants rely on import restrictions through trade remedies rather than devising any strategy to improve their performance.
 - p. The product has been given protection for 10 years, and there cannot be argument for an emergency situation or sudden impairment to the domestic industry for safeguard measures.
 - q. Authority observed in the sunset review investigation that increase in imports pursuant to September 2017 will be on account of demand-supply gap and it did not take into consideration tariff concessions under CEPA.
 - r. The imposition of duty will allow the Applicants to create dominant position for itself in the market and create barriers for new entrants.
 - s. Authority admitted in second sunset review that even if the domestic industry attempted to utilise 100% of the installed capacity, it would not be able to meet the domestic demand and imports pursuant to September 2017 will be on account of demand-supply gap.
 - t. Period of investigation considered at the time of preliminary findings has been extended and modified from the period notified in the initiation notification.

C.4. Increased imports from Korea

12. The submissions made by the Applicants are as follows:

- a. Pursuant to India-Korea CEPA, the duty on imports of Phthalic Anhydride from Korea has been reduced to zero over the years.
- b. There is significant increase in the import volumes. Imports of product under consideration into India increased significantly in absolute terms and in relation to production, consumption and share in imports.
- c. Imports into India from Korea has duty advantage for Phthalic Anhydride under India –Korea CEPA. Hence, the country is now flooded with subject goods from Korea.
- d. India has become a preferred market for the Korean producers as the share of exports to India in the total exports has increased to more than 3 times.
- e. Korean imports enjoyed benefits of huge capacities and low freight cost and are now also aided by custom duty concessions.
- f. Had there been no benchmarking of price by the Korean imports due to duty concessions, the domestic industry would have sold at remunerative prices.
- g. The imports from Korea in absolute terms as well as in relative terms has remained significantly high even in the 3rd and 4th quarter of 2019-20.

13. The submissions made by other interested parties are as follows:

- a. There are no critical conditions for issuance of preliminary finding as the rate of increase in imports is declining whereas in case of other countries it is increasing.
- b. As per Article 3.1 of the Agreement on Safeguards, there must be a reasoned and adequate explanation which demonstrates the connection between the reduction of the duty and the alleged increase in imports. Authority should identify and provide a reasoned explanation and demonstration of the same.
- c. There has been an increase in imports from Thailand and Indonesia as well with whom India has FTA. Further, increase in imports from Taiwan is also in line with increase in imports from Korea.
- d. There has been no recent, sudden, sharp, and significant increase of imports of phthalic anhydride from Korea.
- e. There should be an unforeseen development which should have caused increase in imports.
- f. The increase in imports coincides more with the expiry of the anti-dumping duty on the imports from China PR, Indonesia, Israel, Russia, Taiwan, Thailand and UAE, than the reduction in the custom duties under CEPA. The application is silent on the effects of expiry of anti-dumping duty as a reason for increase in imports.
- g. Imports have not increased in such quantities in the transition period from 2016-17 to 2017-18. There is no correlation between increase in imports and tariff concessions. The increase was due to reason other than CEPA.
- h. Imports from Korea are in proportion to the demand supply gap in India and comparable to other major source of imports like China PR, Thailand and Indonesia. Had elimination of duty been the reason for imports, then the entire imports would have shifted to Korea.
- i. The applicants admitted in the oral hearing that they are uncertain about the cause of imports which could be due to elimination of duties under CEPA, dumping or even subsidy.
- j. Quarter-wise data should have been considered for period for which surge in imports has been claimed by the domestic industry.
- k. Imports were necessitated to meet the demand-supply gap.
- l. While imports from Korea constituted about 23% of the Indian demand, other imports held about 24% of Indian demand.
- m. Imports under advance license must be excluded from total imports.
- n. As per WTO Appellate Body in Argentina Footwear and US – Steel Safeguard, the authority must consider the trend in imports over the period and the increase must be recent.
- o. Absence of price-based injury is also evident as the domestic industry has admitted that it will be in reasonable profits if landed price is increased to Rs 68.97 per MT which is equivalent to landed price of Q1.

- p. Import volumes declined in Q-3 and Q-4 of 2019-20 and the applicants still held more than 50% share in demand.

C.5. Injury

14. The submissions made by the Applicants in respect of injury are as follows:
- a. Production and sales of the Indian industry has declined significantly in the most recent period. While the demand for the product has not increased, the imports have surged, thus adversely impacting the sales volume of the domestic industry.
 - b. Capacity utilization of the industry has declined in Q1 of 2019-20.
 - c. From the decline in production and capacity utilization, it is evident that the increase in imports is causing injury to the domestic industry.
 - d. Market share of domestic industry has declined whereas market share of the imports has increased.
 - e. The subject imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry. The import prices have declined sharply in the last two quarters of Period of Investigation (POI). Thus, if the imports keep on increasing, the domestic industry will not be able to recover even processing costs and would incur significant financial losses.
 - f. The profits of the industry were increasing till Q2 2018-19. The profits of the domestic industry have declined from Q2 2018-19 to Q1 2019-20, considering loss of sales during this period.
 - g. The productivity of the Indian industry has improved initially but declined significantly in the POI.
 - h. In addition to the serious injury already caused, imports are threatening serious injury as would be obvious from the following-
 - i. The volume of imports has increased significantly in a relatively short period.
 - ii. Significant share in the domestic market is already held by the imports and the share of imports is increasing.
 - iii. The difference between domestic price and imported product price is quite significant.
 - i. There are no factors other than increased imports that can be attributed to the serious injury caused to the domestic industry.
 - j. The landed price of imports is significantly lower than the selling prices of the domestic industry.
 - k. The domestic industry is losing sales opportunities as well as normal margin. Consequently, sales, profits, return on investment and cash flow is declining due to continued presence of low-priced imports.
 - l. Increased imports have led to increase in market share of imports and reduction in market share of the domestic industry.
 - m. It is submitted that the imports from Korea have increased significantly whereas the production, sales and resultantly the capacity utilization of Indian industry has declined significantly.
 - n. The production and sales of the domestic industry have remained impacted in the quarter of 2019-20 and the domestic industry has continued to lose margins.
 - o. The domestic industry has the capacity to cater around 70-80% of the market. However, its share has been left restricted to 50-60%.
 - p. Collective share of other country imports in Indian demand is lower than the Korean imports.
 - q. Inventories with the domestic industry have remained higher in the 3rd and 4th quarter of 2019-20.
 - r. Price undercutting in the latest quarter of 2019-20 is historically highest.
 - s. Domestic industry has been forced to export because of the demand for its product in the market. The exports were made at loss marking prices.
 - t. Contrary to the submissions of other interested parties, the imports from other countries have not increased in same line as increase in demand.
 - u. The applicant cannot substantiate the reason for low price of imports but can only request for examination of low price of imports.
 - v. In the past anti-dumping investigations, even though the applicants believed that imports were dumped, negative dumping margin was determined by the Authority for imports from Korea.
 - w. The return on investment of the domestic industry has not only reduced but is negative in some period.

- x. If the domestic industry would have quoted remunerative prices, the price undercutting would have been higher.
 - y. Domestic industry has invested around Rs *** cr in the past on its capacities and is investing another significant amount to cater to demand.
 - z. Landed price of imports from Korea is lower than landed price of imports from non-Korea sources.
 - aa. There is no justification for referring to the injury examined in the anti-dumping investigation on the basis of 2016-17 data.
 - bb. Price underselling or injury margin are not a relevant parameter of injury determination under the safeguard rules.
 - cc. The respondents have provided information with respect to fall in the prices of the subject goods for last few days of 2019-20 only against examination of injury data for 4.5 years.
 - dd. Capacities in the other country are irrelevant for the examination of injury suffered by the domestic industry.
 - ee. Panel in US – Steel Safeguards investigation held that there may be a lag between the influx of imports and the manifestation of the injurious effects on the domestic industry of such an influx. Therefore, though the duties were reduced earlier, there was a gap when the injury was suffered.
 - ff. Any increase in imports due to the requirement of Asian Paints would have been visible in the year 2017-18 itself. However, as compared to 2016-17, imports increased only by 4800 MT.
 - gg. Claims of increase in imports of downstream products are mere conjectures and they are free to approach the Authority for remedy.
 - hh. The decision of Bihar Court in the matter of V Kameshwar Singh AIR 1952 SC 252 aptly highlights that public interest examination does not have any precise definition and therefore in no way is required to be done only considering the user industry.
 - ii. The other interested parties have misquoted the examination of the Authority in the previous investigation. The examination implied that a situation of demand-supply gap will result in imports.
15. The submissions made by the other interested parties in respect of injury are as follows:
- a. The domestic industry itself admits in its petition for the AD investigation that it was performing well and was in profits. Thus, the question of serious injury to the domestic industry on account of concessions granted in the Korea- India CEPA does not arise at all.
 - b. The finding does not meaningfully address whether reduction or elimination of duties under Korea-India CEPA must alone result in an increase in the imports of the subject good, which consequently must be the substantial cause of serious injury to the domestic industry.
 - c. The increase in imports of the product under consideration is not attributable to tariff concessions under the Korea-India CEPA, but a multitude of other factors like demand-supply gap, dumped imports as determined in previous investigations, absence of any correlation between tariff reductions and increase in imports etc.
 - d. The landed price of imports and the selling price of domestic industry in April to September 19 are in same range as compared to 2017-18 wherein negative injury margin was determined. Thus, when the domestic industry was not getting injured in 2017-18, there is no question of injury to the domestic industry for the period April-September 2019.
 - e. The contention of domestic industry that there is no requirement to compare the landed prices from Korea with the NIP of the domestic industry is not consistent with the practice of DGTR and the jurisprudence concerning serious injury. In a determination of ‘serious injury’ it is necessary to compare the landed value of the product under consideration from Korea with the NIP (or fair selling price) of the domestic industry as opposed to the NSR.
 - f. Applicants have claimed injury in the present investigation solely on account of reduction or elimination customs duty whereas, in the anti-dumping investigation recently initiated, it was claimed in the petition that injury was on account of dumped imports. The domestic industry is presenting different and conflicting causes of injury before the Authority. As per Article 2.22, the increase in imports alone be the substantial cause of serious injury or threat of serious injury to the domestic industry.
 - g. Key performance parameters of the domestic industry such as capacity utilization, production, sales, profitability do not show any injury.
 - h. The increase in selling price is more than the increase in landed price.

- i. The Applicants have failed to demonstrate that the alleged injury is due to increase in imports and the reduction in custom duties. It has not been shown that the increase in the imports is due to the reduction or elimination of the customs duties and increase alone is the cause of injury to the domestic industry requirement of Article 2.22 of the India-Korea CEPA.
- j. The discussions in the annual reports of the Applicant do not show any sign of overall deterioration in the situation.
- k. The Applicant should provide data for the injury period determined by the Authority. The period for which data is provided in the Application is misleading.
- l. Data for previous years should have also been considered on quarterly basis. An analysis of annualized data is not practicable or reliable in safeguard investigations as also held by WTO Panel in India- Iron Steel Products
- m. The production of domestic industry has increased. This is in spite of various issues such as volatility in crude oil and other petrochemical products, slow-down in Far East, US-China Trade sanction etc, delay in completing the expansions to meet the demand etc.
- n. Sales of the domestic industry also increased in the latest period in comparison to 2007-08 by 38 points.
- o. There has been an increase in the capacity of the domestic industry. Additions in capacity at a time when the domestic industry is claiming serious injury should be seen as factor demolishing the injury claims of the domestic industry.
- p. The production expansion plans of the Applicants is a sign of domestic industry's judgment that there shall be increase in production and sales volume in the near future which guarantees that there is no serious injury that has been claimed by the domestic industry. In reality, there is a positive outlook.
- q. The import prices have increased following the trend of increase in prices of the domestic industry. The landed price of imports evidently had not forced the domestic industry to reduce its prices. On the contrary, net sales realisation has gone up.
- r. Domestic industry was earning high profits when anti-dumping duty was in force. The fall in current profits is not a decline but correction of abnormally high profits.
- s. In the ADD investigation concluded recently, negative determination on injury was done and likelihood of injury was also ruled out.
- t. Landed price of imports from Korea was higher than various other sources which means that there was no price attractiveness and the total capacity utilization of all exporters is about 99%-100% which rules out any excess unutilized capacity in Korea.
- u. When the domestic industry has been unable to establish serious injury as per CEPA, the claims of threat of serious injury should be taken with much caution.
- v. Price undercutting has reduced after the elimination of duties which shows that it did not lead to reduction in landed price. Prices of domestic industry are very high and are at profitable levels which is the reason for positive undercutting.
- w. While the return on investment has reduced, it is much better than certain historical period wherein the applicants had registered negative returns.
- x. DG has modified period of investigation considered at the time of provisional findings to draw specific conclusions in preliminary findings which would not have been possible otherwise. Period considered for preliminary findings show that period for which the injury is claimed is not in tandem with the period of duty reduction or elimination.
- y. Domestic industry has restricted its argument for loss making export sale to only one quarter which implies that it did not suffer loss making exports in the other 17 quarters.
- z. Recent decline of the domestic industry's performance since the first half of FY2019-20 is not explained with the time of reduction or elimination of duties under CEPA.
- aa. Domestic industry was doing very well in the immediate period after expiry of duties as return on investment reached a historical high level.
- bb. The landed price of imports from Korea have been higher than most of other source of imports ruling out any price injury also from Korean imports.
- cc. Imports from other countries recorded a higher fall in landed price than imports from Korea.

- dd. The price of the product in India was not governed by the landed price of imports. Difference between selling price and landed price could be due to high price charged by the domestic industry.
- ee. Serious injury as per CEPA and the Rules means a significant overall impairment in the position of domestic industry.
- ff. As per WTO Appellate Body in United States – Safeguard measures on imports of fresh, chilled or frozen Lamb meat from New Zealand and Australia, the word serious connotes very high standards of injury. Same view was taken in US Lamb Case for serious injury and threat of injury.
- gg. There are no reasons provided for comparison of annualised data. Comparison does not provide objective evidence unless reasons are provided.
- hh. Preliminary finding is based on the data for 2nd quarter of 2019-20 that sets the tone that the performance of the domestic industry has declined.
- ii. Domestic industry was extremely well in period immediately after elimination of duties and earned 50-60% return on investment in the year in which the duties were eliminated.
- jj. The domestic industry was admittedly in profit till Q1 of 2019-20 as mentioned in anti-dumping petition. Data for Q3 and Q4 should not be considered as they are not part of period of investigation, and for which a parallel application has been filed for anti-dumping duty, where the domestic industry has alleged that injury is solely on account of dumping.
- kk. Authority should examine conditions of competition between the imports and the domestic products to assess injury to the domestic industry.
- ll. Applicants are filing data for quarter 3 and quarter 4 of 2019-20 at such belated stage of investigation.
- mm. Price undercutting reduced after elimination of duties which alone shows that the elimination of duties per se did not lead to any reduction in landed price leading to a higher price undercutting.

C.6. Causal Link

16. The submissions made by the Applicants in respect of causal link are as follows:
- a. In a situation of demand-supply gap, the imports will happen. However, increase in imports from Korea are not in proportion to increase in demand which gets substantiated by the fact that imports from other countries have declined in last 2 years.
 - b. No evidence has been brought forward by other interested parties to show the reason of imports from the subject country.
 - c. Benchmarking of prices only implies that Korean prices act as a standard of prices for other competitors which is the reason of low price of imports from other countries.
 - d. The domestic industry has never informed its customers that it is facing production issues. Consumers may be called on to show communications. Revamp process was carried out when most of the sections of the plant were operational.
 - e. Volatility in crude prices was not faced by the domestic industry alone but by all producers globally. Due to Korean imports, the domestic industry could not align its prices with crude prices.
 - f. Had the increase in imports been due to cessation of duties, the imports would have increased from Taiwan and Israel as well. Major producer from Korea enjoyed nil antidumping duty and therefore, there is no reason to link increase in imports to cessation of duties.
 - g. The performance of the domestic industry in the domestic market is solely dependent on the availability of raw material and competition with imports.
 - h. Contrary claims have been made in respect of Orthoxylene. While some interested parties have argued that the domestic industry faced issues with regard to its supply, others have argued that domestic industry enjoys abundant supply.
 - i. Appellate Body in US – Wheat Gluten took the view that the increased imports should be only one of the causes of injury and need not be the sole reason for the injury and authority need to only assess if there is a "genuine and substantial relationship of cause and effect" between increased imports and serious injury.
17. The submissions made by the other interested parties in respect of causal link are as follows:

- a. Delay in planned capacity expansions, planned short term shut-downs, volatility in the Orthoxylene prices, etc. may also have impacted the performance of the applicants.
- b. Falling difference in the raw material prices and the final product prices influence on performance of the domestic industry.
- c. In the anti-dumping investigation, the reason for injury is dumping from the 4 countries including Korea. Reason for attributing such injury to import on account of reduction/elimination of customs duties is not explained in the preliminary findings.
- d. There has been a sharper increase in imports from ASEAN countries as compared to the subject imports. Therefore, serious injury alone cannot be attributable to subject imports alone.
- e. Production and sales of the domestic industry were impacted because of planned shut down and maintenance, old technology, flash storms and floods. These are admission of fact that there exists injury due to other reasons.
- f. Market reports suggest that import prices for the product under consideration has plummeted recently on the back of grim global economy and crumbled crude futures. Average Indian prices on 20th March 2020 averaged \$720/tonne which was \$100/tonne below where price at month start.
- g. DGTR in the preliminary findings has failed to properly evaluate and assess the plausible alternative explanations with regard to the other factors causing injury.
- h. Authority is required to distinguish effects of different factors and then attribute injurious effects caused by increased imports.
- i. The decline in domestic sales can be attributed to increase in captive consumption.
- j. Applicants had claimed dumping as a cause of injury till the period September 2017.
- k. The production of domestic industry may have been impacted due to supply constraints of Orthoxylene in India.
- l. Applicants have admitted in their annual report that cause of the decline of the performance was the volatility of Crude oil and OX price and the challenges in the global trade environment, east slow down, softening of product prices and destocking by downstream industries. Corrections in margin due to such spread should not be attributed to elimination of duties under CEPA.
- m. If the increase in imports was due to elimination of custom duties, the increase would have been visible from the year 2017-18. The domestic industry was not suffering injury until 2018-19. Increase in imports was more related to the end of anti-dumping duties of imports from Korea, Taiwan, and Israel.
- n. There were supply disruptions due to revamp process and other internal reasons of the applicants which forced users to import as there were no other source of supply.
- o. The CEO of TCL has mentioned in one of his speech that there was lower production and higher costs as the major revamp project was underway.
- p. As per the Investor' presentation of IGPL in August 19, the imports have increased in last 3 years on back of high domestic demand.
- q. The impact of closure of Asian Paints Plant has affected the decline in production and increase in imports, not the reduction of custom duty.
- r. The production of domestic industry has increased by 13 points in the latest period despite various issues such as volatility in crude oil and other petrochemical products, slow-down in Far-East, US-China Trade sanction etc, delay in completing the expansions to meet the demand etc

C.7. Public Interest

18. The submissions made by the Applicants are as follows:
- a. Bilateral Safeguard measures will not stop imports from Korea or any other country and therefore there will be no shortage.
 - b. Domestic industry will be required to compete inter-se and no monopoly will be created in the market.
 - c. There have been multiple trade remedial investigations in the past, but users have never been able to substantiate the adverse impact of duties on them.
 - d. Public interest examinations also need to consider the domestic industry.
 - e. As against the claim that the subject goods are only intermediate products, a fully healthy intermediate industry is equally important for the growth of user industries.

19. The submissions made by other interested parties are as follows:
- The imposition of safeguard measure will seriously damage the downstream growth and impact the prospects of the domestic industry itself.
 - Imposition of duties will be against public interest as there is a demand and supply gap and the goods are used as a chemical intermediate in production of various products.
 - Public interest examination cannot be restricted to domestic industry only but needs to consider interests of larger industry.
 - The imposition of the duty will lead to increase in the price of the imported product which will eventually lead to increase in the prices by the local producers.
 - PAN is not a consumer item and is used to produce variety of value-added products. To give boost to vocal for local campaign, it is imperative to encourage production of value-added products like Phthalate Plasticizers and not burden with excessive taxes.
 - The levy of Safeguard Duty on Phthalic Anhydride will open flood gates for imports of Phthalate Plasticizers which is not in a position to sustain any increase in PAN prices. Phthalate Plasticizers are also currently being imported in India with zero basic customs duty under various FTAs.
 - Value addition in converting the raw materials namely PAN and Oxo Alcohols into phthalate plasticizers is as low as US\$ 50 per tonne and any increase in raw material price will make it difficult to compete with imported phthalate plasticizer.

D. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

20. The information made available by the interested parties in their submissions, have been considered by the Authority for the purpose of the present determination. Further, the Authority notes that different interested parties have advanced similar arguments, albeit in different manner and language. The Authority has examined and addressed the submissions in the present finding. The examination herein below in respect of increase in subject imports, serious injury and causal link ipso facto deals with the submission of applicants and other interested parties.
- The Authority notes that the purpose of the present investigation and proposed measure is required to be considered in right perspective. A concession was earlier given to imports from Korea, in a phased manner, under the trade agreement. The trade agreement provides for invoking safeguard measures and withdrawal of duty concession under certain conditions specified in the agreement. Thus, the objective of the present investigation is not to impose any additional tariff on the Korean imports. The purpose is to only consider whether or not the concession given earlier is required to be withdrawn. Besides, withdrawal of concession would in no way restrict or prohibit the imports into India, either from Korea or from other countries.
 - The Authority notes that imports are inevitable in a situation where the demand for the product is higher than the capacities available in the country. The purpose of the present investigation is not to ban or restrict the imports. However, in a situation where the demand for the product is higher than capacities in India, and there are significant imports into the country, the domestic industry prices get impacted by the landed price of imports. Thus, it is not import volume per se, but the price of imports that is the concern of the domestic industry. The fact is that the landed price of Korean imports by and large became lower than the landed price of non-Korean imports and selling price of the domestic industry. Thus, the domestic industry has been forced to align its prices to the Korean prices and was not able to fully align its prices to the changes in the raw material prices, leading to injury to the domestic industry.
 - As regard the contention that reduction or elimination of duties under Korea-India CEPA must alone result in an increase in the imports of the subject goods, which in turn must be the substantial cause of serious injury to the domestic industry, the Authority notes that the legal provisions under different laws are required to be harmoniously interpreted with regard to the purpose and objective sought to be achieved by these regulations. The authority notes that whether it is dumping or subsidy or tariff concessions, the effect of these is felt by the domestic industry in the form of lower price of imports. Tariff concessions or dumped or subsidized imports ultimately leads to reduced CIF price of imports and consequently reduced landed price of imports. Ultimately, it is the landed price of imports which competes with domestic selling price of the domestic industry. Thus, the relevant factor for consideration of causal link is whether the landed price of import from the subject country is the cause of injury or whether injury to the domestic industry is due to factors other than reduced price of subject imports. Further, in a case, it is also possible that the domestic industry suffers injury not only because of reduced landed price of imports, but also due to other factors, such as plant shut down, lockdown, major maintenance, fire, flood, raw material shortages etc. Thus, the law requires authorities to consider whether the substantial cause of injury to the domestic industry is on account of the reduced landed

price of imports or some other factor. The Authority further notes that reduction in price of imports could be because of tariff concessions or dumping or subsidy, or a combination of some or all of these. The domestic industry in such situations is entitled to seek protection for itself through simultaneous use of all these laws. The only bar under these situations is that the domestic industry cannot seek dual remedy for the same injury. However, this can be appropriately addressed while granting remedy to the domestic industry. It is further noted that the fact that domestic industry might have suffered injury due to dumped imports does not imply that the domestic industry has not suffered injury due to tariff concessions.

- d. The Authority further notes that neither the trade agreement, nor the present rules provide that duty concession should be the sole cause of injury to the domestic industry. The CEPA Agreement provides that increased imports alone should constitute a substantial cause of serious injury or threat thereof to domestic industry producing a like or directly competitive good. The Agreement further provides that a determination that an originating good is being imported as a result of the reduction or elimination of a customs duty provided under the Agreement shall be made only if such reduction or elimination is a cause which contributes significantly to the increase in imports, but need not be equal to or greater than any other cause. Further, the Agreement also provides that the passage of a period of time between the commencement or termination of such reduction or elimination and the increase in imports shall not by itself preclude the determination referred to in the agreement. This clearly implies that increased imports may not be the sole cause of injury. The increased imports alone should be a substantial cause of injury. Even the antidumping rules do not provide that dumping should be the sole cause of injury to the domestic industry. In the present case, for instance, the injury to the domestic industry could be due to both dumping as well as duty concessions. It is quite possible that while some foreign producers resorted to dumping, some did not, even when all of them faced same level of customs duty. The Authority had in fact found during antidumping investigation that the degree of dumping differed materially in respect of different foreign producers.
- e. It is further noted that in order to determine whether and to what extent duty concessions have caused injury to the domestic industry, the Authority has additionally considered the data for longer period by considering the volume of imports and performance of the domestic industry prior to duty concession period, during tariff reduction/elimination period and during post tariff elimination period. The table below shows the factual position. After elimination of customs tariff there is significant increase in imports, both in absolute terms and in relation to production and consumption. While price undercutting was earlier negative, the same has progressively become positive as the duty concession has increased. Further, performance of the domestic industry has declined in the terms of market share and profits over the period. Further, in the most recent period, with further increase in imports, the performance of the domestic industry has declined in terms of production, capacity utilization, domestic sales volume and profit/loss. Thus, performance of domestic industry has shown deterioration with the primary cause being imports from Korea.

Year	Korea Imports	Production	Sales	Market share		Profit/loss	ROI	Price Under-cutting
				Domestic industry	Korea			
	MT	MT Trend	MT Trend	% Range	%	Rs. Lacs - trend	% - trend	% - range
2007-08	14,015	100	100	70-80%	7%	100	100	(10-0)
2008-09	13,938	85	97	70-80%	7%	-142	-46	(10-0)
2009-10	11,420	94	130	70-80%	5%	68	74	(10-0)
2010-11	28,073	94	131	60-70%	10%	7	31	0-10
2011-12	16,183	95	128	65-75%	6%	-31	44	0-10
2012-13	14,409	97	138	60-70%	5%	35	87	0-10
2013-14	18,599	101	137	60-70%	7%	-137	-3	(10-0)
2014-15	15,124	118	158	70-80%	5%	-76	40	(20-10)
2015-16	25,252	124	156	60-70%	8%	132	122	0-10
2016-17	33,766	120	153	60-70%	10%	377	248	5-15

2017-18	41,664	124	160	55-65%	11%	770	353	0-10
2018-19	49,081	120	162	50-60%	13%	537	257	0-10
Q1 2019-20	22,819	113	138	45-55%	23%	34	61	5-15
Q2 2019-20	26,007	108	150	45-55%	25%	-4	9	0-10

- f. With regard the contention that the data provided by the domestic industry does not correspond to the period identified in the initiation notification, it is noted that the application contains data for the period April, 2007 to June, 2019. Further, while responding to initiation, the Applicants have provided data for the period up to Sept, 2019. Thus, the interested parties have access to the relevant information and an opportunity to comment on the information for the said period. The Authority has therefore considered the period from April, 2015 to Sept., 2019 for the purpose of examining increased imports and serious injury to the domestic industry. However, since the interested parties have contended that the Authority is required to consider whether the increase in import is as a result of tariff concessions under the agreement and are consequently causing injury, the Authority has additionally considered the information contained in the application for the period from April, 2007 to June, 2019 to determine whether the increased imports are a result of tariff concession. The period July-Sept., 2019 has also been added considering that this is a safeguard investigation and the Authority in the past has added data for subsequent period, post-initiation of investigation. However, considering the date of initiation, data for the subsequent period (Oct., 2019 – March, 2020) has not been considered for the present purposes.
- g. As regards the submission that adjustment plan was not filed along with the petition originally and hence the initiation is bad in law, it is noted that the requirement of adjustment plan in the application is not with a view to decide on the need for initiation. At the stage of initiation, only such information as is relevant for initiation, is required to be considered. Thus, while Rule 4(2)(b) provides for information on adjustment plan, it does not require the Authority to consider adjustment plan before initiating investigation. Even when application proforma provides for information on adjustment plan, it is noted that the said information is of no utility at the stage of initiation. In fact, the Authority could consider duty even for a period of one year, in which case information on adjustment plan would have been irrelevant. Thus, information on adjustment plan was not critical for a decision on initiation. The said information is relevant for duration of duty at the time of final determination as provided under Rule 10, and not at the stage of initiation. The domestic industry in any case has given an adjustment plan, after initiation of investigation.
- h. As regards the contention that the domestic industry had earlier drawn an adjustment plan which the domestic industry never implemented, the Authority notes that in the instant case, the domestic industry has committed an investment of Rs. *** crores, out of which, the domestic industry has already incurred an amount of Rs. *** crores and has committed an amount of Rs.*** crores. It cannot thus be contended that the domestic industry has not taken any measures to adjust itself.
- i. The Authority notes that the present investigation is a bilateral safeguard investigation initiated under India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 rules read with India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement. The Authority has examined whether or not increased imports are as a result of tariff concessions under the agreement. For this purpose, the Authority has considered imports of the product from April, 2007 to Sept., 2019. It is noted that since 2015-16 the volume of imports has increased in absolute terms and in relation to production and consumption as the tariff concessions increased.
- j. The authority further notes that consideration of imports over the longer period covering pre-duty concession, duty concession and post-duty elimination period clearly shows significant surge in imports. Further, consideration of import in the most recent period further shows a significant surge in import.
- k. As regards imports from non-subject countries, it is seen that the landed price of imports duties are higher from non-subject countries as compared to landed price of imports from Korea. Further, the volume of imports from each of the other countries individually is much lower than the volume of imports from Korea.
- l. As regards imports from ASEAN countries, it is noted that the volume import from ASEAN countries is much lower than volume of imports from Korea both in absolute terms and in relation to production and consumption in India. Further, the increase in imports from ASEAN countries is far lower than the increase in imports from Korea.

- m. As regards the contention that imports have increased because of cessation of anti-dumping duty, the Authority notes that this does not establish that injury is not due to imports from Korea.
- n. As regards the contention that imports have increased due to demand supply gap, the Authority notes that demand supply gap justifies imports per-se. However, landed price of imports from Korea is lower than not only the selling price of domestic industry but also import price from several countries. Further, a number of countries have been supplying the product in Indian market. However, share of import from Korea shows dominant position gained by Korean imports. Further, it is seen that the domestic industry has faced decline in production and domestic sales during the relevant period. Inventory with the domestic industry have increased. These facts show that while the volume of imports is due to demand-supply gap, these imports occurred at a price which caused injury to the domestic industry.
- o. As regards the contention that significant imports have happened under advance authorization scheme, the Authority notes that since imports are under zero duty under the Agreement, it defies the logic why any interested party would import under advance license from Korea and undertake export obligation when the same amount of duty exemption is available without undertaking any export obligation. The information provided by the importers/consumers do not show that a significant volume of Korean imports is under advance licence.
- p. Published unaudited quarterly results of petitioning companies also show significant decline in profits and do not negate the conclusion that the domestic industry prices were impacted by Korean imports.
- q. It has not been established by the interested parties how capacity revamps, delay in planned capacity expansions, planned short term shut-downs etc were the major cause of injury to the domestic industry in pricing its product or selling its production. The injury to the domestic industry is primarily seen in the pricing fetched by the domestic industry and resultant profitability in the product, and its sales volumes & market share and resultant impact on production, capacity utilization, inventories, exports.
- r. As regards volatility of crude prices, the same is a global factor and not peculiar to Indian market. In a free market, the domestic industry would have priced its product duly aligning to such factors.
- s. As regards possible adverse impact on profits due to capacity expansion, it is noted that the performance of the domestic industry in respect of profits and ROI declined steeply in the current period when there was no addition of capacity.
- t. As regards reference to the final findings of the sunset review, it is noted that the sunset review findings are based on April, 2016 to September, 2017 as the investigation period, whereas the injury in the current case is more pronounced in the most recent period and much after the POI investigated in the sunset review. Comparison of costs and prices between the two periods clearly shows that the domestic industry was unable to align its prices to the cost changes and consequently faced significant decline in profits.
- u. The Authority notes that the recommended measure will be limited to only imports from Korea. Imports from all other countries would continue to be made without any safeguard measures. Further, the present measure would not result in imposition of any additional duty. The present investigation was intended to examine whether the duty concession given earlier needs to be withdrawn. Source of supply shall not be curtailed as a result of these measures.
- v. As regards the justification for invoking provisional measures, it is noted that the reasons have been given in the preliminary finding.

The Authority had in the preliminary finding given sufficient justification for considering the 2nd quarter of 2019-20 for injury analysis. It has been a practice to add data for next quarter in the safeguard investigations. As regards inadequate time provided to other interested parties for making submissions on the data for 2nd quarter of 2019-20, it is seen the data was filed by the applicants on 15th January and therefore, other interested parties had sufficient time to file their submissions. In any case, the interested parties were given an opportunity to file their comments on the preliminary finding and thereafter at the time of oral hearing, they had the adequate opportunity to make oral submissions followed by written submissions and rejoinder. The interested parties thus had multiple opportunities to express their views and offer their comments.

- w. As regards the need for imports from Korea due to demand and supply gap and cessation of anti-dumping duties, it is observed that the imports have not increased from all the sources in the same degree as these have from Korea. Suppliers from all sources enjoy equal right in the Indian market. Further, demand-supply gap justifies imports per se. However, the investigation has shown that the domestic industry was not able to align the prices with changes in raw material prices, leading to significant decline in profitability. Further, the trends in other volume parameters also show that the domestic industry has been prevented from selling to the extent it could have, in the absence of

increased Korean imports. Share of imports from Korea shows dominant position gained by the Korean imports, as is evident from the trend of imports over longer period examined at relevant places in the findings.

- x. It was also observed in the sunset review investigation that the majority of exports from Korea was being done by a producer which was attracting nil rate of anti-dumping duty.
- y. As regards the submission that the preliminary findings were recommended after a substantial time, it is seen that there is no time limit prescribed under the CEPA for invoking interim measures, nor does delay in invoking provisional measures cause any prejudice to the interests of Korean suppliers. Further, there is no legal requirement to provide interested parties with an opportunity for oral hearing before the issuance of preliminary finding. Oral hearing is contemplated as a part of process before issuance of final findings. The interested parties have been given an opportunity of being heard. The parties have filed their submissions in writing and the same has been adequately dealt in the present findings.
- z. As regards the import price from non-subject countries, it is not appropriate to compare prices on CIF basis. The prices in the market are required to be compared on the basis of their landed price in India. The fact that prices from other countries have remained in the similar range merely shows, considering the volume of imports from Korea, that the Korean imports acted as a benchmark for the prices from other countries and suppliers. For this reason, even if the import prices from some countries were sporadically lower in a particular period, the same does not imply that these prices were benchmarking the prices in the market. A conclusion is required to be reached, after taking into account facts in entirety, not merely isolated facts. An analysis for the entire period show that the non-subject imports prices were generally higher than the Korean prices.
- aa. As was noted in the preliminary finding, volatility in the crude oil prices is a global factor and not peculiar to Indian market only. The fluctuation in the prices would have affected the Korean producers as well. In a market free from competition with Korean low prices, had there been a fluctuation in the price of the raw material, the domestic industry would have adjusted its prices accordingly. But the domestic industry was prevented from adjusting its prices by the low-priced imports from Korea. There is significant positive undercutting which shows that had the domestic industry aligned its prices with raw material changes, it would have lost further sales.
- bb. As regards the submission of other interested parties that the comparison of annualized data is not adequate, the Authority notes that it has compared the data on an actual basis. However, wherever length of the period is different, the same has been annualized while comparing with the data for other period.
- cc. As regards the submission about duties being against public interest, it is noted that interested parties making these submissions have not given any verifiable information/ evidence demonstrating how invoking measures will be against public interest. The Govt. had earlier twice imposed global safeguard measures on this product, after finding the imposition of safeguard duty to be in the public interest. The present recommendation is not for imposition of additional duty. It is for withdrawal of a concession given earlier. Even otherwise, the scope of public interest is much larger and is not limited to the interests of consumers of the subject goods only. The measure is only against the Korean imports. Even these imports will continue, albeit at MFN rate of customs duty. All other sources of imports are open. It is also seen that the domestic industry is expanding its capacity and there will be additional material available in the domestic market.
- dd. The measures including the anti-dumping duty and the BIS measures are not protection to the domestic industry. BIS is implemented for different objective and applies on non-discriminatory basis. Anti-dumping duty can be invoked only to the extent of margin of dumping and is meant to restrict unfair trade practice. The purpose of these measures is to not kill competition but to ensure fair competition in the market.
- ee. The Authority notes that non-injurious price is calculated to determine injury margin in pursuance of lesser duty rule followed by India under anti-dumping mechanism. However, the present investigation is a bilateral safeguard investigation and there is no requirement to calculate non-injurious price or injury margin in such investigation.
- ff. It is seen that the captive consumption of the domestic industry is very minimal and could not have been a cause of injury to the domestic industry.
- gg. It is clarified that the Authority has considered actual data for the present determination. However, wherever the length of the period is not 12 months, the same is annualised while comparing with other periods of 12 months as per the established practice in order to ensure that the comparison is not flawed due to different lengths of periods.

- hh. In relation to the submission that the imports did not increase with changes in customs duty, the Authority considers that a conclusion is required to be reached after taking into account the entirety of the period. There may be other factors as well at that point of time (for example, existing safeguard duty or ADD in some of the periods). Consideration of data over longer period, including the period of pre-concession, concession and post-concession phase, it is seen that the Korean imports of the product have increased in absolute and relative terms.
- ii. As regards injury suffered by the domestic industry due to other factors, it is seen that no substantiated information or evidence has been brought on record to show that the primary cause of injury is such other factor.
- jj. As regards the submission that the prices have globally declined in the end of March 2020, it is noted that the trend of imports and the economic parameters of the domestic industry has been examined over long period. Decline in prices, even if a global phenomenon, is required to be addressed, particularly when landed price of imports from Korea were lower than landed price of imports from other countries. The prices in the domestic market are a factor of import prices and cost of raw material. Therefore, fall in prices in the global market would not have affected the domestic prices as much, had the imports not entered at concessional duty.
- kk. It has been submitted by various interested parties that the domestic industry has been protected with trade remedial investigations over the past decade. Authority notes that it would not be appropriate to treat trade remedy actions as a protection, nor these actions are invoked only because the domestic industry has requested. These measures are invoked after following a quasi-judicial investigation with participation of all interested parties, and after due examination of merits, and in due compliance to the law.
- ll. It has been stated that the decrease in exports to other countries has no relevance to exports to India. The domestic industry has contended that whereas imports into India have increased, exports to other countries have declined.
- mm. As regards the claim that there is minor decline in profits, it is noted that the decline in profits is significant. In fact, the domestic industry suffered losses in Q-2 of 2019-20.

D.1. Product under consideration

- 21. The product under consideration in the present investigation "Phthalic Anhydride" (also referred to as PAN) falling under the tariff heading 29173500 is an anhydride of Phthalic Acid and is commercially produced by catalytic oxidation of Ortho-xylene or Naphthalene.
- 22. Phthalic Anhydride is a colourless solid. It is also described as Phthalic Anhydride flakes, Phthalic Anhydride (98% min.), Phthalic Acid Anhydrous, Phthalic Anhydride (99.8% min), etc.
- 23. Phthalic Anhydride is used to produce Phthalate esters, which function as plasticizers. Further, it is a chemical intermediate in plastic industry.

D.2. Domestic industry

- 24. The Rule 2(b) Bilateral Safeguard Measures Rules, 2007 states as follows: -
"domestic industry" means the producers -
 - (i) as a whole of the like or directly competitive goods operating in the territory of India; or
 - (ii) whose collective output of the like or directly competitive goods constitutes a major proportion of the total domestic production of those goods;
- 25. The present application has been filed by M/S IG Petrochemicals Ltd. and M/s Thirumalai Chemicals Ltd. SI Group Pvt. Ltd. is the only other known producer of the product in India. SI Group Pvt. Ltd. filed information in the prescribed format after initiation of investigations, but after expiry of the time limits. It is noted that no submissions have been made by either the Applicants or the interested parties over the scope of the domestic industry during the course of the investigations. Applicants' production constitutes a major share in gross Indian production. The application satisfies the requirement of standing under the Rules. Further, IG Petrochemicals Ltd. and M/s Thirumalai Chemicals Ltd. constitute domestic industry for the purpose of the present investigation.

D.3. Period of investigation

- 26. The period considered at the stage of initiation was April, 2015 to June, 2019. Further, since this is a safeguard investigation, considering the past practice, the Authority considered the data for the period up to September, 2019 for the preliminary finding. The domestic industry provided data for the period up to March 2020. However, the Authority has already added data for the period up to September, 2019, the same was made

available to the interested parties by the domestic industry as well as through preliminary findings, the investigation was initiated in October, 2019 and hence it is not appropriate to consider data for the period subsequent to initiation. Therefore, the data for the period subsequent to September, 2019 has not been considered in the present findings. Further, since the interested parties have raised concerns whether imports have increased as a result of concessions and whether the performance of the domestic industry has deteriorated due to duty concessions, the Authority has also considered the data for the period from 2007-08, which was part of the application.

D.4. Confidentiality

27. Rule 6 of the Rules deals with confidentiality of information. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non - confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential versions of the evidence submitted by various interested parties in the form of public file.

D.5. Customs duty under Comprehensive Economic Partnership Agreement

28. The rate of custom duty on the imports of Phthalic Anhydride considering the concessions under the Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Korea was as follows: -

Applicable Customs duty rate			
31 st Dec 2009	10.94%	2010-11	10.55%
31 st Dec 2010	9.38%	2011-12	8.99%
31 st Dec 2011	7.81%	2012-13	7.42%
31 st Dec 2012	6.25%	2013-14	5.86%
31 st Dec 2013	4.69%	2014-15	4.30%
31 st Dec 2014	3.13%	2015-16	2.74%
31 st Dec 2015	1.56%	2016-17	1.17%
31 st Dec 2016	0.00%	2017-18	0.00%
31 st Dec 2017	0.00%	2018-19	0.00%
31 st Dec 2018	0.00%	2019-20	0.00%

D.6. Source of information

29. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume and value of imports. Injury information has been considered from the application filed by the domestic industry. Information since 2007-08 has been considered from the application filed by the domestic industry.

a. Imports from Korea in absolute terms:

30. The movement of imports is shown in the table below:

SN	Year	Import volume	Trend	Customs duty
		MT	Index	
1	2015-16	25,252	100	2.74%
2	2016-17	33,766	134	1.17%
3	2017-18	41,664	165	0.00%
4	2018-19	49,081	194	0.00%
5	Apr'19-Jun'19	22,819	361	0.00%
6	Jul'19-Sep'19	26,007	412	0.00%

31. It is seen that the imports of the product under consideration have increased significantly over the years.

b. Imports in relation to gross imports in India

32. The share of imports of subject goods from Korea and other countries is shown in the table below:

S.No.	Year	Imports in MT			Share in imports	
		Korea	Other countries	Total imports	Korea	Other countries
1	2015-16	25,252	53,866	79,118	32%	68%
2	2016-17	33,766	58,285	92,051	37%	63%
3	2017-18	41,664	88,775	1,30,439	32%	68%
4	2018-19	49,081	95,579	1,44,660	34%	66%
5	Apr'19-Jun'19	22,819	23,384	46,204	49%	51%
6	Jul'19-Sep'19	26,007	23,830	49,837	52%	48%

33. It is seen that share of imports of the product under consideration from Korea increased over the period with the rising tariff concession whereas the share of other countries declined. The imports from Korea now command majority share with the duty concession increasing to its full extent. Even when imports are being reported from a number of other countries, their share collectively is lower than share of Korea alone.

c. Increase in imports in relation to production and consumption in India

34. The movement of imports of subject goods in relation to production and consumption in India is shown in the table below:

S.No.	Particulars	Korea imports	Indian Production	Demand	Imports in relation to	
					Production	Consumption
		MT	MT	MT	%	%
1	2015-16	25,252	3,07,008	3,32,413	8%	8%
2	2016-17	33,766	2,96,561	3,39,251	11%	10%
3	2017-18	41,664	2,89,491	3,72,030	14%	11%
4	2018-19	49,081	2,75,492	3,82,583	18%	13%
5	Apr'19-Jun'19	22,819	65,086	97,163	35%	23%
6	Jul'19-Sep'19	26,007	62,061	1,05,209	42%	25%

35. It is seen that the imports have increased significantly in relation to production and consumption with the increase in duty concessions.

D.7. Injury

36. Serious Injury is defined as follows under the Rules:

(f) *serious injury means a significant overall impairment in the position of a domestic industry; and*

(g) *"threat of serious injury" means serious injury that, on the basis of facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility, is clearly imminent; and*

37. Thus, increase in imports should be such which has caused a significant overall impairment in the position of a domestic industry.

38. Rule 7 of the Rules further provides as follows:

The Authority shall determine serious injury or threat of serious injury to the domestic industry taking into account, inter alia, the following principles, namely:

(a) *the Authority shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the originating good in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports of the*

originating good, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilisation, profits and losses, and employment; and

(b) the determination under this rule shall not be made unless the investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the originating good and serious injury or threat thereof and when factors other than increased imports of the originating good are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports of the originating goods.

39. It is noted that evaluation of the listed parameters needs to take into account peculiarities of different industries and situations. The Authority has examined serious injury to the domestic industry, having regard to the facts of the present case and the situation of the industry. Thus, in addition to a technical examination of all the listed factors and any other relevant factors, it is essential that the overall position of the industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry. Accordingly, in analyzing serious injury all factors, which are mentioned in the rules as well as other factors which are relevant for determination of serious injury, have been considered.

a. **Increase in imports in absolute and relative terms**

40. It is seen that the imports of subject goods have increased significantly in absolute term as well as in relation to production and consumption in India. It is also seen that the imports increased significantly with the full concessions given to the Korean imports.

b. **Capacity, Production, Capacity Utilization and Domestic Sales**

41. The details of capacity, capacity utilization and domestic sales are as follows:

SN	Years	Capacity	Production	Capacity Utilisation	Domestic sales	Export	Korea imports
		MT Trend	MT Trend	%-Trend	MT Trend	MT Trend	MT
1	2015-16	100	100	100	100	100	25,252
2	2016-17	100	97	97	98	103	33,766
3	2017-18	100	100	100	102	98	41,664
4	2018-19	100	97	98	104	63	49,081
5	Apr-Jun'19	100	91	92	89	70	22,819
6	Jul-Sep'19	100	87	88	96	92	26,007

42. It is seen that: -

- a. Production and capacity utilisation of the domestic industry has declined over the period;
- b. Domestic sales of the domestic industry increased till 2018-19 but have declined thereafter.
- c. Export sales declined till 2018-19, but increased thereafter. The applicant has claimed that it was forced to export because of imports from subject country. It is seen that the profitability of exports is much adverse as compared to domestic sales.

c. **Market share of the domestic industry**

43. The movement of market share was as follows:

SN	Particulars	Domestic industry (Range)	Korean imports	Other Producers (Range)	Other Countries	Total
1	2015-16	60-70%	8%	5-15%	16%	100%
2	2016-17	60-70%	10%	5-15%	17%	100%
3	2017-18	55-65%	11%	0-10%	24%	100%
4	2018-19	55-65%	13%	0-10%	25%	100%
5	Apr'19-Jun'19	45-55%	23%	0-10%	24%	100%
6	Jul'19-Sep'19	45-55%	25%	0-10%	23%	100%

44. It is seen that whereas market share of domestic industry declined, that of Korean imports increased. On overall basis, whereas the domestic industry lost 16% market share over the period, the Korean imports gained the market share by almost the same level.

d. Employment and Productivity

45. The data on employment and productivity is as follows-

S.No.	Year	No. of Employees	Productivity per day	Productivity per employee
		Trend	MT/Day Trend	MT/Nos. Trend
1	2015-16	100	100	100
2	2016-17	100	97	97
3	2017-18	101	100	99
4	2018-19	103	97	95
5	Apr'19-Jun'19	103	92	89
6	Jul'19-Sep'19	103	87	85

46. The productivity per day and productivity per employee has witnessed decline in the recent years. The applicants have however submitted that performance on these accounts are dependent on a number of other parameters and is not directly linked to import competition.

e. Inventory

47. The data on inventory shows as follows-

SN	Particulars	Average stock (MT) Trend
1	2015-16	100
2	2016-17	121
3	2017-18	72
4	2018-19	71
5	Apr'19-Jun'19	140
6	Jul'19-Sep'19	132

48. It is seen that the level of inventories with the domestic industry increased over the period.

f. Profit/loss

49. The data on profits and return on capital employed shows as follows-

SN	Year	Profit/(loss)		ROI
		Rs. Lacs - trend	Rs/MT - trend	
1	2015-16	100	100	100
2	2016-17	285	291	205
3	2017-18	584	570	295
4	2018-19	407	392	216
5	Apr'19-Jun'19	104	467	53
6	Jul'19-Sep'19	-13	-54	5

50. It is seen that the profits and return on capital employed have steeply deteriorated post 2017-18. The domestic industry suffered financial losses in the most recent period of July to September, 2019.

g. Price undercutting

51. The Authority examined whether the imports from Korea were benchmarking the prices of the product in the market. For the purpose, the Authority compared the landed price of imports from various countries with the landed price of imports from Korea and selling price of domestic industry.

S.No.	Year	NSR	Landed price	Price Undercutting	Price Undercutting
		Rs/MT - trend	Rs/MT	Rs/MT	% Range
1	2015-16	100	56,387	***	0-10%
2	2016-17	113	61,185	***	5-15%
3	2017-18	119	66,989	***	0-10%
4	2018-19	135	74,225	***	0-10%
5	Apr'19-Jun'19	126	68,900	***	5-15%
6	Jul'19-Sep'19	112	63,618	***	0-10%
7	April to Sept.,19	119	66,086	***	0-10%

52. It is seen that the landed price of imports has been below the selling price of the domestic industry. Imports were thus undercutting the domestic industry prices.
53. The Authority examined the trends in cost of production, selling price of the domestic industry with the landed price of imports from Korea. It is seen that whereas the landed price of imports was earlier above the cost of sales, in the recent period, the landed price of imports are below the cost of sales. Had the domestic industry sold at these import prices, it would have suffered losses in the current period.

SN	Year	Cost of Sale	Selling price	Landed price
		Rs/MT - trend	Rs/MT - trend	Rs/MT
1	2015-16	100	100	56,387
2	2016-17	105	113	61,185
3	2017-18	99	119	66,989
4	2018-19	123	135	74,225
5	Apr'19-Jun'19	127	126	68,900
6	Jul'19-Sep'19	118	112	63,618
7	April to Sept.,19	122	119	66,086

E. CONCLUSION

54. It is concluded that the imports of the product under consideration have increased significantly in absolute terms and in relation to gross imports in India, Indian production and consumption. Imports were undercutting the domestic prices. Landed price of imports were below the cost of sales of the domestic industry. As a result of significant surge in imports from Korea, the performance of the domestic industry has deteriorated, as seen in decline in production, sales, capacity utilization, market share, profit, ROI, rising less profitable exports and rising inventories. Considering the performance of the domestic producer in respect of various parameters, it is concluded, that the domestic industry has suffered serious injury as a result of duty concessions granted to Korean imports leading to increased imports of the product under consideration from Korea at low prices.

F. THREAT OF SERIOUS INJURY

55. The Rules provides as follows:

"threat of serious injury" means serious injury that is clearly imminent and shall be determined on the basis of facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility"

56. It is noted that imports of subject goods from Korea are entering the Indian market in significantly increased quantities in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India. The domestic industry's capacity was underutilized and the intensified imports from Korea has adversely impacted the situation. Considering the difference between Korean and domestic industry price , capacities with Korea and export volumes from Korea it is evident that the subject goods from Korea are likely to remain price attractive, posing continued threat of injury to the domestic industry. The threat of serious injury is established by the following factors: -

- a. The price difference between the domestic and imported product has led to increase in imports of subject goods from Korea.
- b. The producers from Korea are holding significant unutilized capacities.
- c. There is an increase in exports from Korea to India and decline in exports to the rest of the world.
- d. The demand of the product is growing and the Indian market is large and price sensitive.
- e. The volume of imports continued to remain high and performance of the domestic industry continued to remain adverse in the recent period.

In view of above it is concluded that the increased imports of subject goods from Korea have also caused threat of serious injury to the domestic industry.

G. CAUSAL LINK

57. A comprehensive evaluation of performance of the domestic industry, as brought out hereinabove demonstrates that domestic industry has suffered serious injury and is threatened with further serious injury by increased imports from Korea. The Authority examined whether the injury to the domestic industry is due to duty concessions and consequent increase in imports from Korea. Additionally, in view of the arguments of the interested parties that the Authority is required to examine whether the claimed injury is on account of duty concessions or some other factors, the Authority also considered the performance of the domestic industry over longer period, including the period when there was no duty concession. Relevant information on this account is contained in the application filed by the domestic industry, which is also accessible to the interested parties through non-confidential version of the application and submissions.

- a. The Authority examined whether any other factor could have caused serious injury to the domestic industry. The Authority considered various known parameters and the factors brought by the interested parties and concluded that the reported injury to the domestic industry is not due to existence of other factors operating at the same time.
- b. The imports of product from Korea have increased significantly with increase in tariff concessions to the Korean imports and its eventual elimination of customs duty.
- c. With full duty concessions, the landed price of Korean import is lower than the selling price of the domestic industry. It was the Korean prices which were benchmarking the prices of the product in the market.
- d. The landed price of Korean imports is now below the cost of sales of the domestic industry.
- e. The capacity utilization of the domestic industry is below the optimum level and as a result production has declined. The production and domestic sales of the domestic industry have declined with rising imports as a consequence of duty concessions. The decline in domestic sales and rising inventories are a result of increase in imports in India.

58. It is thus evident that injury to the domestic industry has been caused by the increased imports and there is a causal link between increased imports of subject goods from Korea and serious injury and threat of serious injury to the domestic industry as a result of duty concessions granted to Korean imports.

H. ADJUSTMENT PLAN

59. Applicants have provided details of the adjustment plan during the course of the investigation. The Domestic Industry has submitted that it is taking measures directed towards reducing costs as mentioned in adjustment plan. Regarding adjustment plan given by the domestic industry, the Authority notes as under. .
- IG Petrochemicals Limited has drawn an adjustment plan which includes action on reduction in raw material cost by replacement of existing catalyst, improvement in recoveries, reduction in power & fuel cost, capacity additions and integrating utilities of existing plants, reduction of costs on account of administrative overheads, personnel cost and finance cost. It is seen that the company has drawn a plan to expand capacity by 53,000 MT at a capital expenditure of Rs *** cr. This would result in significant cost reduction for the company.
 - Thirumalai Chemicals has drawn an adjustment plan which includes reduction in cost by upgrading equipment for higher capacity & efficiency, improvement in yield, reduction in energy costs, reduction in oil consumption, reduction in wages & salaries, stores & spares, repair & maintenance and administrative overheads. The company has reported to have drawn a plan to expand capacity by 1,20,000 MT. The company has committed a capital expenditure of Rs *** cr. This would result in significant cost reduction to the company.
60. The Authority notes that the applicants have drawn adjustment plan to become competitive vis-a- vis Korean imports.

I. PUBLIC INTEREST

61. Interested parties have contended that imposition of safeguard duty would severely prejudice the public interest as a number of end user industries would be impacted. It has also been argued that the imposition of safeguard measures would make it costlier and this would be against consumer interest. Concerns have also been raised about the demand and supply gap in the country.
62. The Authority notes that the present measures are not directed towards imposing any additional duty but only towards withdrawal of concession given earlier, that too in respect of imports from Korea alone. Imports from all other sources are totally unaffected by the proposed measures.
63. As regards concerns of inadequate domestic capacity to cater to the demand, it is noted that the domestic industry could have met higher percentage of domestic demand in the absence of Korean imports. Imports from Korea in any case shall continue to be available at MFN rate of customs duty even after imposition of proposed measure. Further, imports from all other sources shall also remain accessible. It is also noted that the domestic industry is expanding its capacity. Post completion of expansion, the gross Indian capacity for the product shall be 4,84,000 MT, as against existing demand of 4,04,744 MT. Imports in any case are open from all sources to the consumers in case of demand exceeding domestic capacities.
64. The Authority notes that none of the interested parties have provided any verifiable evidence and information on how invoking present bilateral measures will lead to unbearable adverse impact. The interested parties have only made assertions that the product is an intermediate product and the imposition of duties will have an impact on the user industry. But these parties have not presented any relevant data. It is further noted that global safeguard measures have earlier also imposed on the product after due examination of public interest.

J. CONCLUSION AND RECOMMENDATION

65. On the basis of the examination above, it is concluded that increased imports of subject goods have caused serious injury to the domestic industry. With regard to imposition of bilateral safeguard measure, Rule 10 of India – Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 states as follows:

(1) The Director General shall, within eight months from the date of initiation of the investigation, or within an extended period not exceeding one year from the date of initiation of the investigation, as the Central Government may allow, determine whether-

(a) the increased imports of the originating good under investigation has caused or threatened to cause serious injury to the domestic industry; and

(b) a causal link exists between the increased imports of the originating good due to the reduction or elimination of a custom duty under the Trade Agreement and serious injury or threat of serious injury.

(2) The Director General shall also give his recommendation regarding bilateral safeguard measure which would be adequate to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment.

(3) The Director General shall also make his recommendations regarding the duration of the bilateral safeguard measure:

Provided that where the period recommended is more than one year, the Director General may also recommend progressive liberalisation of the bilateral safeguard measure at regular intervals during the period of application, adequate to facilitate adjustment.

66. After examining the above, it is concluded that
- imports of the product from Korea have increased and constitute “increased imports” within the meaning of the Rules and Korea-India CEPA.
 - The increased imports has caused serious injury and threatened to cause serious injury to the domestic industry,
 - there exists a causal link between the increased imports of the originating good due to the reduction or elimination of a custom duty under the Korea-India CEPA and serious injury and threat of serious injury to the domestic industry.
67. It is considered appropriate to recommend bilateral safeguard measure in terms of Rule 10 of India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017. Accordingly, the Authority recommends increasing the rate of customs duty on imports of subject goods originating in Korea RP to the level of Most Favoured Nation applied rate of customs duty on the subject goods as on the date of application of Bilateral safeguard measure or Most Favoured Nation applied rate of customs duty on the subject goods on the day immediately preceding the date of entry into force of the Trade Agreement, whichever is less. The measure is recommended for a period of two years as per table below from the date of issue of the notification of imposition of provisional duty by the Central Government vide Notification No.29/2020-Customs dated 6th July, 2020.

Year	Bilateral Safeguard measures
First year	Increase the rate of customs duty @ 100% to the level of Most Favoured Nation applied rate of customs duty
Second year	Increase the rate of customs duty @ 75% to the level of Most Favoured Nation applied rate of customs duty

68. Subject to the above, the Preliminary Finding notified vide notification dated 11th May, 2020 is hereby confirmed.

B.B.SWAIN, Spl. Secy. & Director General